मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

मुल्य : 3 रुपए

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 1-15 NOVEMBER 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 / संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com / Help Line 9878552070

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री ने शाहपुर कंड़ी डैम प्रोजेक्ट जनता को किया समर्पित

3394.49 करोड़ रुपए की लागत वाला प्रोजेक्ट, जिसमें 80% योगदान पंजाब का, शाहपुर कंड़ी प्रोजेक्ट से राज्य को मिलेगी बिजली और सिंचाई की व्यापक सुविधा

एस. के. सक्सैना

पठानकोट, पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 3394.49 करोड़ रुपए की लागत वाले शाहपुर कंड़ी डैम प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक परियोजना राज्य में बिजली और सिंचाई की सुविधाओं में बड़ा इज़ाफा करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन देश, विशेषकर पंजाब के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने इस डैम के निर्माण में योगदान देने वाले इंजीनियरों, कर्मचारियों और श्रमिकों का समूचे पंजाब की ओर से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिन–रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को साकार किया। उन्होंने कहा कि यह डैम किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और आम जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि प्रधान राज्य पंजाब को इस डैम से सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि इससे जहां बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस परियोजना से युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा 卐शाहपुर कंड़ी डैम पंजाब, विशेषकर माझा क्षेत्र की (लाइफ लाइन)जीवन रेखा साबित होगा। मुझे विश्वास है कि यह डैम न सिर्फ लाखों घरों को रोशन करेगा बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों में उजाला भरेगा। न्होंने बताया कि शाहपुर कंड़ी डैम प्रोजेक्ट की कुल लागत 3394.49 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2694.02 करोड़ रुपए (लगभग 80त्न) पंजाब सरकार द्वारा और 700.45 करोड़ रुपए (20त्न) केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए कुल 3171.72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें से 1643.77 एकड़ पंजाब और 1527.95 एकड़ जम्मू–कश्मीर क्षेत्र की है। नए डैम से सिंचाई सुविधा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पंजाब के 5000 हेक्टेयर (12,500 एकड़) क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर समेत माझा क्षेत्र के अन्य जिलों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त अप्पर बारी दोआब नहर के अधीन एक लाख 18 हजार हेक्टेयर भूमि को अब निरंतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शाहपुर कंड़ी डैम के निर्माण से पहले रणजीत सागर डैम पावर हाउस सुबह और शाम की उच्च मांग के समय अपनी पूरी 600 मेगावाट क्षमता से काम नहीं कर सकता था, क्योंकि नीचे पानी संग्रहित करने के लिए कोई जलाशय नहीं था और पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था। अब शाहपुर कंड़ी डैम के शुरू होने से रणजीत सागर पावर हाउस प्रभावशाली रूप से बिजली उत्पादन कर रहा है, और वहां से छोड़ा गया पानी शाहपुर कंड़ी जलाशय में संग्रहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए स्थिर पानी आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डैम की ऊंचाई 55.5 मीटर है और इसमें 7.7 किलोमीटर लंबी हाइडल चैनल बनाई जा रही है। दो पावर हाउस (206 मेगावाट कुल क्षमता) बनाए जा रहे हैं, जिनका 75त्न कार्य पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसके बाद बिजली उत्पादन शुरू होगा।

एनडीए की जीत पर भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी

गमछा घुमाकर किया भीड़ का अभिवादन

पटना (एजंसी)– बिहार चुनाव में राजग की जीत पर 'मोदी, मोदी, 'भारत माता की जय के नारों और पार्टी कार्यकर्ताओं की जय–जयकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में उनका स्वागत किया। इस मौके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारी जीत और अटूट समर्थन ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया। लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक विकसित और समृद्ध बिहार के लिए वोट दिया है। इस जीत ने हमें बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए

उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजग के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। राजग के सभी सहयोगियों की ओर से, मैं बिहार की सारी जनता को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में नतमस्तक हूं। कुछ पार्टियों ने 'एमवाई% का तुष्टीकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन इस जीत ने महिला और युवा के नए %एमवाई% संयोजन को मजबूत किया है। मैं रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग में विश्वास जताने के लिए लोगों को बधाई देता हूं। वहीं, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत के लिए मैं करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। बिहार के जनादेश ने 'जंगलराज% के लिए 'नो एंट्री% का बोर्ड लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है। लोगों ने चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार अटूट विश्वास दिखाया है, चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या अब बिहार हो।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुरूवार को भोपाल स्थित सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए- छात्र-छात्राओं को किया संबोधित

रमन कुमार

नई दिल्ली–केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुरूवार को भोपाल की सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह ने पीएचडी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास छात्र–छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने छात्र–छात्राओं और उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि, दीक्षांत समारोह दीक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि ये दिन सिर्फ डिग्री लेने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने का दिन है। आज से असली जीवन की परीक्षा शुरू होती है। जहां ज्ञान को कर्म में बदलना है, समाज और देश की सेवा में लगाना है। यहीं से तय होता है कि, आपने जो सीखा है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगा या जीवन और राष्ट्र निर्माण का साधन बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, दीक्षांत नहीं, ये तो नवदीक्षा का पर्व है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का क्षण है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र–छात्राओं से कहा कि, बड़ा सोचा, अच्छा सोचा, बड़े सपने देखो, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। उन्होंने कहा कि, जिंदगी के जिस भी मोड़ पर जरूरत होगी, इनोवेटिव आइडिया हो तो मेरे पास भेजना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यहां भोपाल में भी मामा का घर है और दिल्ली में भी मामा का घर है, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि, मेरे लिए राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की सेवा का माध्यम है। सार्थक और सफल मानव जीवन वही है जिसमें दूसरों की सेवा हो, क्योंकि मेरे लिए लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, स्वामी विवेकानंद के शब्द आज साकार हो रहे हैं। सवा सौ साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो

सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि, भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्व गुरू के पद पर अधिष्ठित हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेन्द्र था, तो एक नरेन्द्र ने सवा सौ साल परले य कहा था और एक नरेन्द्र यानी कि, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी, इसे साकार कर रहे हैं। यह हमारी आंखों के सामने होगा, कोई रोक नहीं सकता।

विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया

कानूनी तरीके से ही विदेश जाएं– प्रवासी भारतीयों के संरक्षक महानिदेशक, श्री सुरिंदर भगत

पंकज

जालंधर, विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीयों के संरक्षक महानिदेशक श्री सुरिंदर भगत ने पंजाब और देश के युवाओं से अपील की है कि वे विदेश जाने के लिए अवैध रास्तों की बजाय कानूनी और सुरक्षित तरीकों का ही पालन करें। आज जालंधर में आयोजित 卐सुरक्षित और कानूनी प्रवासन卐 (सुरक्षित और कानूनी प्रवासन से संबंधित जागरूकता अभियान) पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भगत ने कहा कि जो भी व्यक्ति बेहतर संभावनाओं के लिए विदेश जाना चाहता है, उसे किसी भी ट्रैवल एजेंट की सेवाएं लेने से पहले उसके प्रमाणपत्रों और विश्वसनीयता की जांच अवश्य करनी चाहिए। ह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), जालंधर द्वारा प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमीग्रेंट्स, चंडीगढ़ के सहयोग से सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन्स, शाहपुर, जालंधर में आयोजित किया गया। यह पंजाब में शुरू की गई पहली ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, कानूनी और जागरूक प्रवासन अवसरों के बारे में जन–जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को अवैध प्रवासन व फर्जी रोजगार प्रस्तावों के खतरों से सचेत करना है। कार्यक्रम के दौरान श्री भगत ने कानूनी प्रवासन पर पंजाबी भाषा में एक विशेष जानकारी पुस्तिका तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डिजिटल जागरूकता अभियान के लिए सङ्कद्वस्त्रद्गह्यद्धक्रश्5द्दड्डह्म्स्ड्डह्लद्धद्ब हैशटैग का शुभारंभ किया। उनके साथ प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स, चंडीगढ़, श्री यशु दीप सिंह; सहायक निदेशक, सीबीसी, श्री राजेश बाली; अतिरिक्त उपायुक्त, श्रीमती अमनिंदर कौर बराड़; तथा पुलिस अधीक्षक, श्री सरबजीत राय भी उपस्थित थे। श्री यशु दीप ने कहा कि राज्य के अन्य

जिलों में भी जल्द ही ऐसे और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे विभाग की वेबसाइट 222.द्वद्वद्वद्दह्म्ड्डह्लद्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाएं और परवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) के व्हाट्सऐप नंबर 74283–21144 पर संपर्क कर विदेश जाने से जुड़ी सभी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने युवाओं को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे चल रहे कार्यक्रमों का लाभ उठाएं जो छात्रों और प्रवास की इच्छा रखने वाले युवाओं को प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकृत चैनलों की जानकारी प्रदान करते हैं। सीबीसी की टीम द्वारा अवैध तरीके से विदेश जाने के दुष्परिणामों पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही, कानूनी प्रवासन के तरीकों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन (पीटीपीआर) के अंतर्गत पंजीकृत कई वीज़ा कंसल्टेंट्स ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री भगत ने किया। इसमें सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के मार्गों पर आधारित जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित किए गए। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सूचना स्टॉल भी लगाए गए थे, ताकि प्रतिभागी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि सरकारी विभागों, भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि युवाओं और छात्रों को प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुरूप उचित जानकारी, पर्याप्त कौशल और सुरक्षित एवं अधिकृत चैनलों के माध्यम से प्रवास के अवसर प्राप्त हो सकें। यह जनसंपर्क पहल विदेश मंत्रालय की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो 卐सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं卐 के विज़न को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नागरिकों के सुरक्षित, कानूनी और कुशल प्रवासन को प्रोत्साहित करती है।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा अभियान

रमेश बाबा

जम्मू–यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर समय–समय पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। इसी सुरक्षा पहल के तहत, आज, 13 नवंबर, 2025 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, डॉग स्क्वायड और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। इस सुरक्षा अभियान के तहत, जम्मू रेलवे स्टेशन और आसपास के रेलवे परिसर की गहन जाँच की गई। यात्रियों के सामान, प्लेटफार्मों और आने–जाने वाली ट्रेनों की मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड द्वारा चैक किया गया। प्रतीक्षालय, आरक्षण काउंटर, बुकिंग कार्यालय और पार्सल कार्यालय का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। जम्मू रेलवे स्टेशन पर चलाए गए

सुरक्षा अभियान के तहत, यात्रियों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी बताया गया। इस विशेष सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, रेलवे स्टेशन पर सामान्य रेल यातायात सुनिश्चित हो। जिससे की यात्रियों को कोई असुविधा न पहुंचे। मंडल के अधिकारियों द्वारा स्टेशन पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को भी ड्यूटी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों से अपील की जाती हैं, कि अपनी यात्रा के दौरान सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुए, बल्कि तुरंत सुरक्षा कर्मियों तथा रेलवे की हेल्प लाइन नंबर 139 व 182 पर सूचित करें।

जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाने में धमाका, 9 की मौत

घटना के वक्त हरियाणा में बरामद विस्फोटकों की जांच कर रही थी टीम

जम्मू (एजंसी)–श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात हुए एक आकस्मिक विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिसकर्मी हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थ के नमूने ले रहे थे। यह सामग्री 'सफेदपोश' आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ी जांच का हिस्सा थी। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में अधिकांश पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। घटना के बाद अब तक आठ शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि घायलों को श्रीनगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह विस्फोट गिरफ्तार चिकित्सक मुजम्मिल गनई के किराए के मकान से बरामद किए गए 360 किलोग्राम विस्फोटक के नमूने लेते समय हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वहां मौजूद वाहन और पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। बम निरोधक दस्ते को भी लगातार हो रहे छोटे विस्फोटों के कारण बचाव अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश अक्टूबर में तब हुआ था जब नौगाम के बनपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले जैश–ए–मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच के बाद तीन स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर शोपियां के मौलवी इरफान अहमद और फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। विश्वविद्यालय परिसर से अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर सहित बड़ी मात्रा में रसायन बरामद किए गए।

संपादकीय

??

???

भारत के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने हेतु हडको ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, ः श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ओडिशा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (मुंबई), मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो समुद्री और कोस्टल इंफास्ट्रक्चर में अपने वित्तपोषण पोर्टफोलियो का विस्तार करने के हडको के प्रयासों में एक प्रमुख उपलब्धि साबित हुआ। मुंबई में चल रहे मैरिटाइम सप्ताह 2025 के दौरान, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नवरत्न एनबीएफसी–आईएफसी ने अगले दशक के लिए भारत के पोर्ट इंफास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1.1 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ छह समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक पहल माननीय प्रधानमंत्री के बंदरगाह–आधारित विकास को बढ़ावा देने और भारत के कोस्टलाइन और जलमार्गों की क्षमता को दिशा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस अवसर पर, श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी, हडको ने कहा, फ्बंदरगाह वित्तपोषण में हडको की प्रविष्टि हमारी विकास यात्रा में एक नया अध्याय है। इन कार्यनीतिक सहयोगों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य सागरमाला कार्यक्रम और मैरिटाइम अमृत काल विजन 2047, समुद्री परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए भारत के समुद्री इंफास्ट्रक्चर में 1.1 लाख करोड़ का निवेश करना है, दोनों का उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैरिटाइम हब में बदलना है। भारत का बंदरगाह क्षेत्र आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और बेहतर दक्षता के कारण बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्रचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, औसत वैसल टर्नअराउंड समय लगभग आधा रह गया है, जो ग्लोबल मैरिटाइम क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी

खिलाड़ी के रूप मंे भारत को रेखांकित करता है। हडको का बंदरगाह वित्तपोषण में प्रवेश एक ऐसे कार्यनीतिक मोड़ पर हुआ है जब मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 में बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में 3–3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। सरकार की पहल जैसे 25,000 करोड़ रुपये की मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ), 24,736 करोड़ रुपये की शिपबिल्डिंग फाइनैंशियल असिस्टेंस स्कीम (एसबीएफएएस), और 19,989 करोड़ रुपये की शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (एसबीडीएस), का उद्देश्य बंदरगाह–आधारित विकास को सुदृढ़ करना, शिपबिल्डिंग क्षमता को बढ़ाना और सतत् मैरिटाइम इंफास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।

इस पहल के रूप में, हडको ने भारत के समुद्री परिदृश्य में बड़े पैमाने पर निवेश के अवसरों को अनलॉक करने के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और संस्थानों के साथ साझेदारी की हैः

* सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (एसएफसीएल)ः हडको और एसएफसीएल संयुक्त रूप से सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं के लिए अगले दशक में 80,000 करोड़ रुपये तक का विस्तार करेंगे, जो बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ाने और लॉजिसटिक्स लागत को कम करने पर केंद्रित है।

* जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए)ः मौजूदा टर्मिनलों के पुनर्वित्तपोषण, पुनः आबंटित पीपीपी परियोजनाओं के वित्तपोषण और आगामी विस्तार प्रयासों के समर्थन के लिए 5,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

* वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल)ः हडको ने 21 जनवरी, 2025 को भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह – ग्रीनफील्ड वधावन पोर्ट, जिसे वैश्विक व्यापार के लिए भविष्य के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

– मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण (एमबीपीए)ः यह समझौता ज्ञापन मुंबई में एक समुद्री प्रतिष्ठित संरचना की योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो भारत की मैरिटाइम हैरिटेज की उपलब्धि को प्रस्तुत करने का एक ऐतिहासिक व्यापार और पर्यटन केंद्र है।

– विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण (वीपीए)ः इस 487 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बर्थों का मशीनीकरण, पीपीपी मोड के तहत आधुनिकीकरण और लिक्विड कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव करना है।

– पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (पीपीए)ः बर्थ मशीनीकरण, नए डॉक कॉम्प्लेक्स और कंटेनर टर्मिनलों के वित्तपोषण के लिए 5,100 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 2030 तक पीपीए की क्षमता को 400 एमएमटी तक बढ़ाने में सहायता करेगा।

– श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता (एसएमपी–कोलकाता)ः 3,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन से पूर्वी भारत के समुद्री संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत बर्थ, कंटेनर टर्मिनल और लिक्विड कार्गो जेटी के पुनर्निर्माण और मशीनीकरण को वित्तपोषित किया जाएगा।

हडको ने हाल के वर्षों में असाधारण वित्तीय प्रदर्शन भी दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2024–25 में, कंपनी ने ?2,709 करोड़, अब तक का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वर्ष–दर–वर्ष 28ब की वृद्धि दर्शाता है, साथ ही प्रचालन राजस्व में 32.46ब की वृद्धि भी दर्शाता है। ऋण पुस्तिका में 34.72ब की वृद्धि हुई, जो ?1,24,828 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे प्रूडेंट वित्तीय प्रबंधन और नए इंफास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कार्यनीतिक विविधीकरण का समर्थन प्राप्त हुआ।

इस पहल के साथ, हडको भारत के मैरिटाइम और इंफास्ट्रक्चर के परिवर्तन में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है – देश की विशाल कोस्टलाइन के साथ विकास, कनेक्टिविटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

मोगा की बेटी हरमनप्रीत ने रचा इतिहास, 47 साल बाद भारत को दिलाया वर्ल्ड कप

कैप्टन.सुभाष चंद्र शर्मा
ब्यूरो चीफ

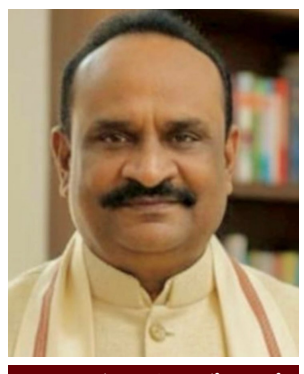

मोगा की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल बाद महिला वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, बल्कि पंजाब और खास तौर पर मोगा के लिए गौरव का क्षण है, जहां से हरमनप्रीत ने अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी। पंजाब भाजपा प्रदेश सचिव दुर्गेश शर्मा ने हरमनप्रीत कौर को बधाई देते हुए कहा कि, फ्मोगा की बेटी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। हरमनप्रीत ने पंजाब की बेटियों के हौसले को नई उड़ान दी है। यह जीत न केवल भारतीय महिला क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।फ्र शर्मा ने कहा कि मोगा की गलियों से शुरू हुआ हरमनप्रीत का

भाजपा प्रदेश सचिव दुर्गेश शर्मा बोले–हरमनप्रीत ने पंजाब की बेटियों के हौसले को नई उड़ान दी

सफर आज विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंच गया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हरमनप्रीत का संघर्ष और समर्पण हर उस बेटी के लिए संदेश है जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखती है। आज पूरा पंजाब उन पर गर्व महसूस कर रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा सुधार किया-पंकज कुमार

मनदीप कौर

जालंधर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के क्षेत्रीय आयुक्त श्री पंकज कुमार ने जानकारी दी कि संगठन द्वारा पीएफ से आंशिक निकासी के पुराने 13 जटिल प्रावधानों को सरल बनाते हुए अब उन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में एकीकृत कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार आंशिक निकासी की श्रेणियां निम्नलिखित हैं –

1. जरूरी आवश्यकताएं – जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि।

2. आवास संबंधी आवश्यकताएं – मकान क्रय, निर्माण या मरम्मत हेतु।

3. विशेष परिस्थितियां – जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी इत्यादि।

इन संशोधनों का उद्देश्य सदस्य खाताधारकों को अधिक सुविधा और वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, अब सदस्य बीमारी, शिक्षा या विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए पहली श्रेणी के अंतर्गत निकासी कर सकेंगे, जबकि मकान संबंधी खर्चों के लिए अलग श्रेणी उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय आयुक्त श्री पंकज कुमार ने बताया कि अब किसी भी आंशिक निकासी के लिए सदस्य की न्यूनतम सेवा अवधि केवल 12 महीने निर्धारित की गई है। पहले यह अवधि इससे अधिक थी, लेकिन नए नियमों के तहत केवल एक वर्ष की सेवा के बाद निकासी संभव होगी।

उन्होंने बताया कि शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है।

शिक्षा के लिए अब सदस्य 10 बार तक निकासी कर सकते हैं।

ज़ विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति है।

पहले इन दोनों उद्देश्यों के लिए संयुक्त रूप से केवल तीन बार तक निकासी की अनुमति थी। क्षेत्रीय आयुक्त श्री पंकज कुमार ने बताया कि सदस्य अब अपने खाते से कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों के योगदान सहित पात्र राशि (100ब) तक निकासी कर सकते हैं। केवल यह शर्त रखी गई है कि खाते में न्यूनतम 25ब राशि बनी रहनी चाहिए। शेष 25ब राशि पर पूर्ववत 8.25ब वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा, जिससे सदस्य की सेवानिवृत्ति निधि का लाभ भी सुरक्षित रहेगा।

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियां’ श्रेणी में अब किसी दस्तावेज़ या कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले प्राकृतिक आपदा, फैक्ट्री बंद होने या बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य था, किंतु अब सदस्य बिना औपचारिकता के भी राशि निकाल सकेंगे।

नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम सेटलमेंट (Premature Withdrawal) की अवधि को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है (पहले यह 2 महीने थी)। इसी प्रकार, अंतिम पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इन सुधारों से सदस्यों को आपात वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक समय और सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति योजना भी सुरक्षित बनी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत EPS–95 पेंशनधारियों को उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र की लागत ?50 होगी, जिसे श्र्क्रन्नह स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार पेंशनधारियों को इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस- पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 15-दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की

सभी तहसीलों से श्री आनंदपुर साहिब तक निःशुल्क बस सेवा की जाएगी प्रारंभ

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब सरकार द्वारा नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अमर विरासत को नमन करते हुए उनकी अद्वितीय शहादत, सत्य के मार्ग पर चलने के सिद्धांत और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को समस्त मानवता तक पहुँचाने के लिए गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार श्री दीपक बाली के साथ आज पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत किसी एक धर्म या सम्प्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मौलिक अधिकारों और सम्मान के लिए थी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गुरु साहिब जी की अमर शहादत के बारे में पंजाब और देश के हर कोने तक जानकारी पहुँचे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस महान बलिदान से प्रेरणा ले सकें। व्यापक और विभिन्न स्मृति कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि शहीदी दिवस को समर्पित आयोजन 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रारंभ होंगे।

इन कार्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग, विशेष रूप से युवा और विद्यार्थी, इसमें भाग ले सकें। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर से पंजाब के सभी स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक 15–दिवसीय अनिवार्य शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रातःकालीन सभा के दौरान 10–12 मिनट का पूर्व–रिकॉर्ड किया गया पाठ प्रसारित किया जाएगा जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शहादत और खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बताया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से अवगत कराना है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 350वें शहीदी दिवस को समर्पित सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने संस्थानों द्वारा दिखाई गई उत्साही प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत को उजागर करता 45 मिनट का विशेष लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर को पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट से होगी, जिसके बाद यह शो राज्य के अन्य जिलों में भी प्रस्तुत किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों से निकाले जाने वाले चार नगर कीर्तन के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहला नगर कीर्तन 19 नवंबर को गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) से आरंभ होगा। इस नगर कीर्तन में पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल, जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल होंगे, जबकि शेष तीन नगर कीर्तन फरीदकोट, बठिंडा और गुरदासपुर से प्रारंभ होंगे। चारों नगर कीर्तन 22 नवंबर की शाम को श्री आनंदपुर साहिब पहुँचेंगे। इन नगर कीर्तनों के दौरान सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी सेवक के रूप में सेवा निभाएंगे। स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाए गए पवित्र नगर श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक 350वें शहीदी पर्व को समर्पित मुख्य आयोजन होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत 23 नवंबर को अखंड पाठ साहिब से होगी, जिसके उपरांत सर्व धर्म सम्मेलन, विरासत–ए–खालसा में प्रदर्शनी, सायं 5 बजे गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन और बलिदान पर आधारित देश का पहला ड्रोन शो तथा शाम 6 बजे कीर्तन दरबार आयोजित होगा। दिन का समापन फ्शहादत दी लौफ्र के साथ होगा, जिसके अंतर्गत मशालों से पूरे नगर को आलोकित किया जाएगा।

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञिापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अंतरराष्ट्रीय पावर स्लैप विजेता जुझार सिंह का सम्मान किया

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने आज अपने कक्ष में जुझार सिंह पुत्र संगत सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया। जुझार सिंह अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पावर स्लैप चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और विश्व के पहले सिख खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने रूसी हैवीवेट खिलाड़ी अनातोली गालुश्का को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जुझार सिंह श्री चमकौर साहिब, जिला रूपनगर के रहने वाले हैं। स्पीकर संधवां ने कहा कि जुझार सिंह ने खेलों के प्रति अपनी लगन और समर्पण के बल पर विश्व स्तर पर पंजाबियों का नाम रोशन किया

है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी पंजाब की खेल पहचान को पूरी दुनिया में नई ऊँचाइयों तक पहुँचा रहे हैं। संधवां ने जुझार सिंह को इस क्षेत्र में और अधिक सफलता प्राप्त करने तथा अपने खेल में शीर्ष स्थान हासिल करने की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार खेलों के स्तर को ऊँचा उठाने के साथ–साथ खिलाड़ियों की भलाई के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि खेल नशे की समस्या को समाप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं, और हमारे युवाओं को जुझार सिंह जैसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

हरियाणा ख़बरनामा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

1-15 November 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

हरियाणा कैबिनेट ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 से कपल केस क्लॉज हटाने को मंजूरी दी

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रोसेस में और ज़्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 में एक संशोधन को मंज़ूरी दी गई। ऐसे कर्मचारी जिसका जीवनसाथी हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनात है, उसे 5 अंक दिए जाएँगे। इसके अलावा, योग्यता अंक दंपति सहित हरियाणा सरकार के दो कर्मचारियों में से केवल एक को ही दिए जाएँगे। हरियाणा कैबिनेट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों के लिए रोज़गार–सहायता को मंज़ूरी दी चंडीगढ़, 3 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के परिवारों, चाहे उनकी मृत्यु हरियाणा राज्य में हुई हो या इससे बाहर हुई हो, ऐसे परिवारों के एक मौजूदा सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोज़गार देने के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति देने की नीति, 2022 में संशोधन को मंज़ूरी प्रदान की। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2025 को हरियाणा विधानसभा में की गई घोषणा को क्रियान्वित करेगा, जो पीड़ित परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संशोधन के तहत, नीति में एक नया क्लॉज़ जोड़ा गया है, जिसके तहत दंगा पीड़ितों के 卐सर्वसम्मति से चयन किए गए मौजूदा परिवार के एक सदस्य के नाम को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से लेवल–I, लेवल–II, या लेवल–ⅢⅢⅢ कैटेगरी में उपयुक्त जॉब के लिए विचार किया जाएगा, जो एचकेआरएन द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगा। यदि किसी विभाग में सभी पद भरे हुए हैं, तो एचकेआरएन पात्र व्यक्ति को रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विभाग में या अपने ही संस्थान में समायोजित किया जाएगा। यह अनुकंपा प्रक्रिया एचकेआरएन के माध्यम से रोज़गार के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है, जो 1984 के दंगों के दौरान अपूर्णीय क्षति सहन करने वाले परिवारों के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करेगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1963 अधिनियम और 1965 नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दी

चण्डीगढ़, 3 नवंबर – भारत सरकार ने अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्त व्यवस्था के माध्यम से व्यापार में आसानी (ईओडीबी) सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसका उद्देश्य नियामक ढाँचों को युक्तिसंगत बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में विलंब को संशोधन अधिसूचित विकास योजनाओं में भूमि उपयोग क्षेत्रों के अनुरूप स्व–प्रमाणन के अंतर्गत एक प्रणाली शुरू करने के लिए किए गए हैं। यह प्रणाली पात्र आवेदकों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों और स्वचालित सत्यापन के आधार पर ऑनलाइन

हरियाणा में व्यवसाय सुगमता ढाँचे को मज़बूत करने हेतु संशोधन

कम करना है। इस पहल के तहत, 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से आठ हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से संबंधित हैं। इसीके अनुरूप, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 8(1 और 2) तथा नियम 2, 26ए और 26ई (3) में संशोधन के संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उक्त स्व–प्रमाणन के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी आएगी और राज्य में कारोबार करने में आसानी होगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाने गए इस ईओडीबी सुधार को लागू करने के लिए, एक मसौदा अध्यादेश – हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025 तैयार किया गया

हरियाणा लिख रहा है समृद्धि की नई परिभाषा- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

59 वर्षों की विकास यात्रा ने हरियाणा को खुशहाली तक पहुंचाया –मुख्यमंत्री, 60वें हरियाणा दिवस के समापन पर मुख्यमंत्री बोले – हरियाणा विकास, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक बना

मनदीप कौर

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा इस बात की गवाही देती है कि हरियाणा ने सम्पन्नता और खुशहाली तक का लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश में इन्फास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इन्फास्ट्रक्चर और इन्क्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास। चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। मुख्यमंत्री सोमवार को यवनिका गार्डन, सेक्टर–5 में 60वें हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव एवं प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि तीन दिनों तक चले इस उत्सव में हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास यात्रा को न केवल देखा, बल्कि महसूस भी किया। हमारे कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले कलाकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह तीन दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह हरियाणा की आत्मा का उत्सव है। विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक दिखाई। इन सबने इस उत्सव को जन–जन का उत्सव बना दिया और हमारी संस्कृति और लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया और इस उत्सव को यादगार बना दिया। उन्होने कहा कि इस बार का नवंबर उत्सवों का माह बन गया है। पिछले तीन दिन पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। दो दिन बाद ही 5 नवंबर को प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव भी 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। 21 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को मिलेगा। मैं इन सब पर्वो की आप सबको अग्रिम रूप से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी माह हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिकता की तरंगों में सराबोर होने का समय है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत और जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत है। लेकिन आज देश की जी.डी.पी. में प्रदेश का योगदान 3.6 प्रतिशत है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक, लगभग 3 लाख 53 हजार रुपये है, जबकि 1966 में यह मात्र 343 रुपये थी। उस समय प्रदेश का निर्यात मात्र 4 करोड़ 50 लाख रुपये था, जो अब बढ़कर 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रहण में भी हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यून–500 कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। उन्होने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। गन्ने का भाव सर्वाधिक 415 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार हमने सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 3 हजार 200 रुपये मासिक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खा?द्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। वर्ष 1966 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 206 लाख टन हो गया है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहीवाल गायों से दूध–दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नाममात्र थे। वहां अब हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। अब गांव व ढाणी भी बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं, राज्य के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन उपलब्ध हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आई.टी. और अन्य उ?द्योगों का बड़ा केन्द्र है। इसका श्रेय हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों को जाता है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इन्फास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज प्रदेश में चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, रेलमार्ग व मैट्रो रेल का जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाई ओवर जनता का जीवन सुगम बना रहे हैं।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के भव्य आयोजन के लिए सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन

सभी दलों ने एकमत से कार्यक्रमों को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का लिया प्रण

पंकज

चंडीगढ़, – नौवें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के भव्य आयोजन के लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री कृष्ण जमालपुर, इनेलो के गुरविंदर धमीजा, जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री ब्रज शर्मा, आम आदमी पार्टी से श्री सुशील गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में सभी नेताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने कार्यक्रम की श्रृंखला में अन्य कार्यक्रमों को शामिल करने के साथ–साथ सभी कार्यक्रमों को मर्यादापूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के सुझाव दिए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लिया और हर संभव सहयोग देने का ऐलान किया। बैठक में बताया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के इस भव्य आयोजन के दौरान प्रदेश में चार प्रमुख यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा सिरसा के रोड़ी से 8 नवंबर को आरंभ होगी। सभी ने सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया कि जहां–जहां गुरु साहिबान के चरण पड़े, वहां से यात्रा गुजरे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन को भी यात्राओं से जोड़ा जाये। बैठक में आये एक महत्वपूर्ण सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा गया कि 350 कन्याओं द्वारा मुख्य कार्यक्रम में गुरु कीर्तन किया जायेगा। बैठक में डॉ प्रभलीन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने हरियाणा की भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया। इन स्थानों पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे, उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं सभी दलों ने एकमत से श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उनके 350वें शहीदी वर्ष को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लिया।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने अम्बाला को दी पांच और नई एसी ई-बसों की सौगात, कुल 15 बसों से अब लोकल सफर बनेगा कूल और ग्रीन

रमन कुमार

चंडीगढ़, – हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला में पर्यावरण के अनुकूल लोकल/शहरी बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला में पांच और नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों (ई–बस) को लोकल रुट पर शामिल किया गया है। 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पहे ही किया जा रहा है। अब पांच नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने पर बसों की संख्या कुल 15 हो गई है जोकि पर्यावरण तो स्वछ और सफर को आरामदायक बनाऐंगी। उन्होंने बताया कि महानगरों की तर्ज पर अम्बाला में भी लोकल बस सेवा को पूरी तरह से वातानुकूलित ई–बस सेवा में बदलने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के अम्बाला में लोकल बस रुट पर आधुनिक 23 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। इन बस क्यू शेल्टरों में लोगों के बैठने के साथ–साथ बिजली व लाइट की सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि इस समय लोकल परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए कुल 25 बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें 15 इलेक्ट्रिक एसी बसें शामिल है। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला में लोकल बस सेवा को लगभग 25 वर्षों बाद पुनः प्रारंभ किया जा सका है। श्री विज ने बीते वर्ष 1 नवंबर को 10 मिनी बसों के साथ परिवहन सेवा की शुरूआत की थी। इसके बाद इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को लोकल बस सेवा में 5

बसों के रुट पर 23 आधुनिक बस क्यू शेल्टर का भी हो रहा निर्माण, बैठने की व्यवस्था के साथ पंखे व लाइट की सुविधा भी होगी – अनिल विज

इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल किया गया था। अम्बाला में इन रुटों पर चल रही लोकल बस सेवा

यात्रियों के लिए 23 स्थानों पर आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण शुरू – विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोकल बस सेवा का लाभ अधिक से अधिक यात्रियों को बिना किसी दुख तकलीफ के मिले यही हमारी प्राथमिकता है। सर्दी–गर्मी और बरसात के मौसम भी यात्रियों को दिक्कत न हो इसके लिए अम्बाला छावनी में नगर परिषद द्वारा 23 स्थानों पर आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक क्यू शेल्टर बैठने के अलावा लाइट व पंखे की व्यवस्था से युक्त होंगे।

नौ दिन में 2165 अपराधी सलाखों के पीछे

कैथल (एजंसी)–हरियाणा पुलिस का स्पेशल मिशन 'ऑपरेशन ट्रैक–डाउन' अब राज्य के इतिहास की सबसे आक्रामक एंटी–क्राइम कार्रवाई बन चुका है। सिर्फ 9 दिनों में पुलिस ने 2165 अपराधियों को सलाखों के पीछे ठूंसकर साफ संदेश दे दिया है कि हरियाणा में अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। बड़े गैंगों से लेकर अंतरराज्यीय अपराधियों तक, किसी को भी कानून से भागने की मोहलत नहीं दी गई। बहादुरगढ़ यूनिट की स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस अभियान में सबसे बड़ा वार करते हुए रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात सदस्य मनोज उर्फ चोटिया को गिरफ्तार किया। इस पर 10,000 का इनाम था और यह कई संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। मनोज उर्फ चोटिया ने 5 दिसंबर, 2024 को नारनौल अदालत परिसर में गैंगवार की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था।

राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात

एस. के. सक्सैना

राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष जीवानंद शर्मा ने दिल्ली में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की गतिविधियों को मंजूरी देने के संबंध में चर्चा की।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री

मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया, जो शांति और भाईचारे के आधार हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व शांति की भावना को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष ने संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सुनील भारद्वाज जी और उनके द्वारा समाज और पूरे भारत में भगवान परशुराम जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में भी चर्चा की। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष श्री ओपींदर शर्मा भी उपस्थित थे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एनआईटी जालंधर ने ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया

मनदीप कौर

जालंधर, डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर (एनआईटीजे) ने 27 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का सफलतापूर्वक समापन किया। इस दौरान संस्थान में कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जो इस वर्ष की थीम 卐सतर्कता- हमारी साझा जिम्मेदारी卐 के अनुरूप थीं। सप्ताह की मुख्य विशेषता श्री इंदर राज सिंह बैंस, एक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी, जो लोक अदालत जालंधर के अध्यक्ष और जालंधर को–ऑपरेटिव बैंक के सीईओ–सह–सतर्कता अधिकारी रहे हैं, का प्रेरक संबोधन रहा। 卐जीरो टॉलरेंस- सतर्कता को सबकी जिम्मेदारी बनाना卐 विषय पर बोलते हुए श्री बैंस ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाई दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने दर्शकों से जीवन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रमों के दौरान छात्रों ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें जागरूक करने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे कार्टून और पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दिए और एक ईमानदार भारत की झलक पेश की। इसी तरह पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को पारदर्शी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिता में भी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेता पोस्टर, नारे और कार्टून प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किए गए, जिससे सप्ताह का संदेश और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचा। इस अवसर पर प्रो.अनीश सचदेवा, डीन (छात्र कल्याण) ने फैकल्टी और स्टाफ को शपथ दिलाई, और सभी को नैतिक मूल्यों का पालन करने का संकल्प दिलाया। । इस अवसर पर, निदेशक प्रो. बिनोद कुमर कनौजिया ने कहा, 卐यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारे मूल संस्थागत मूल्यों की पुष्टि है। हम सतर्कता और ईमानदारी को हमारी परिसर संस्कृति के मूल ताने–बाने में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे छात्र न केवल कुशल इंजीनियर बनें, बल्कि नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक भी बनें। पूरे सप्ताह छात्रों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी ने यह दिखाया कि एनआईटी जालंधर नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और सतर्कता की भावना को अपने संस्थागत जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए जारी किया 332 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक फंड-हरपाल सिंह चीमा

कहा, 334 करोड़ रुपये की अगली किश्त दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी, फंडों के दुरुपयोग पर केंद्रीय राज्य रेल मंत्री की गलत जानकारी की निंदा की, एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली का दिया हवाला

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करने, आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण किश्त जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसी श्रृंखला में 334 करोड़ रुपये की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह बना रहे। पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत यह राशि ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों, जैसे कि सैनिटेशन बॉक्स की स्थापना आदि के लिए उपयोग की जाएगी। जारी किए गए फंडों का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 332 करोड़ रुपये की राशि को रणनीतिक रूप से टाइड और अनटाइड फंडों में विभाजित किया गया है ताकि सामान्य स्थानीय विकास और विशेष स्वच्छता कार्य दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि 156 करोड़ रुपये की ग्रांट अनटाइड फंड के रूप में दी जा रही है, जिसे ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में उपयोग कर सकती हैं। वहीं 176 करोड़ रुपये की राशि टाइड फंड के रूप में स्वच्छता कार्यों के लिए निर्धारित की गई है। यह संपूर्ण ग्रांट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच 70-20-10 के अनुपात में वितरित की जाएगी।

जिला–वार वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 22 जिलों में कुल 3,329,750,900 रुपये (जिसमें 1,766,319,970 रुपये टाइड फंड और 1,563,430,930 रुपये अनटाइड फंड शामिल हैं) आवंटित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक राशि वाले जिले लुधियाना (टाइड 200,143,127 रुपए , अनटाइड 133,905,292 रुपए), होशियारपुर (टाइड 170,847,451 रुपए, अनटाइड 114305, 089 रूपये और गुरदासपुर (टाइड 165563,924 रुपए, अनटाइड 110770,166 रुपए) हैं। अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोज़पुर, फाज़िल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियाँ उनकी 卐जानकारी की कमी卐 और एस एन ए स्पर्श प्रणाली की समझ के अभाव को दर्शाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का योगदान (केंद्र–राज्य साझेदारी अनुपात के अनुसार) जमा कराने के बाद भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी सीधे आर बी आई खाते में जमा करवाती है। इस प्रकार एस एन ए स्पर्श प्रणाली केंद्र और राज्य सरकार दोनों के फंडों से वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित करती है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने रवनीत बिट्टू से अपील की कि वे गलत जानकारी फैलाने से बचें और राजपुरा–चंडीगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की लेआउट योजना को सार्वजनिक करें, यदि केंद्र सरकार ने वास्तव में राज्य के साथ इसे साझा किया है। अपने संबोधन का समापन करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ग्राम पंचायतों तक सीधे और जवाबदेह वित्तीय प्रवाह के माध्यम से साफ़–सुथरे, मज़बूत और जीवंत ग्रामीण समुदायों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार वर्तमान में 4,150 करोड़ रुपए की लागत से 19,000 किलोमीटर सड़कों की पुनः–कारपेटिंग जैसे बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्ट चला रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार खेल स्टेडियमों के निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और लगभग 250 खेल नर्सरियों की स्थापना भी कर चुकी है, जिससे राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

एसवीएसयू के मॉडल पर बनेगी बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी

बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने किया एसवीएसयू का अवलोकन,बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अधिकारी रहे शामिल

पलवल, प्रमोद कौशिक - बिहार सरकार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मॉडल पर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। बुधवार को बिहार सरकार के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद के नेतृत्व में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दुधौला परिसर का भ्रमण किया और कौशल आधारित दोहरी शिक्षा प्रणाली के इस मॉडल का अवलोकन किया। यहां पहुंचने पर कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार एवं कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया और उन्हें इस मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बिहार से आए प्रतिनिधिमंडल को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का दौरा करवाया और उन्हें यहां स्थापित विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक पर आधारित लैब दिखाई। उनके साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग और पढ़ाई के साथ–साथ कमाई के मॉडल पर भी चर्चा की। बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने डाइकिन इंडिया और ऊषा सिलाई मशीन की ओर से स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस भी देखे। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ड्रोन, ईवी और वेल्डिंग आधारित प्रोजेक्ट देख कर बिहार से आए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जम कर सराहना की। उन्होंने लैब में काम कर रहे विद्यार्थियों से संवाद भी किया और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारियां हासिल की। इस प्रतिनिधिमंडल में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद के अतिरिक्त बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के निदेशक गीतेश गुंजन और सीनियर कंसल्टेंट नीरज कुमार झा भी शामिल थे। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के इंडस्ट्री के साथ समन्वय से लेकर भविष्य की योजनाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप केजी टू पीजी मॉडल पर चर्चा की। अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर विक्रम सिंह ने स्किल यूनिवर्सिटी का पूरा मॉडल विस्तार से उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने विजन–मिशन से लेकर क्लास रूम और इंडस्ट्री के समन्वय के बारे में बताया। प्रोफेसर विक्रम सिंह ने बिहार से आए अधिकारियों को विश्वविद्यालय की अवधारणा एवं स्थापना से लेकर समस्त जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस मॉडल में विद्यार्थी 40 प्रतिशत थ्योरी कलस रूम में पढ़ते हैं और 60 फीसदी इंडस्ट्री में जाकर सीखते हैं और इस दौरान उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस मॉडल की विशेषताओं की सराहना की और बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना में इसे महत्वपूर्ण बताया। कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा में अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, प्रोफेसर कुलवंत सिंह, प्रोफेसर सुनील गर्ग, प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर डीवी पाठक, संयुक्त निदेशक शिखा गुप्ता, उप कुलसचिव डॉ. ललित शर्मा, डॉ. विकास भदौरिया, अमिष अमेय, डॉ. सविता शर्मा, डॉ. श्रुति गुप्ता, डॉ. संजय राठौड़, डॉ. मनी कंवर, डॉ. रविंद्र कुमार, डॉ. दलीप रैना, डॉ. नकुल, ओएसडी संजीव तायल, एसडीओ नरेश संधू और नीरज पराशर सहित कई अन्य शिक्षक एवं अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का अवलोकन करते बिहार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एवं साथ में कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार।

गुरू गोबिंद सिंह स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो में उमड़ा संगत का सैलाब

15 हजार से अधिक ने की शिरकत, पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरू तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें वर्ष को समर्पित समागम

एस. के. सक्सैना

जालंधर, –पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के 350वें वर्ष को समर्पित समागमों की श्रृंखला के तहत मंगलवार शाम को स्थानीय गुरू गोबिंद सिंह स्टेडियम में शानदार लाइट एंड साउंड शो करवाया गया, जिसमें 15 हजार से अधिक संगत ने शिरकत की। पंजाब सरकार द्वारा यह समागम श्री गुरू तेग बहादुर जी, जिन्होंने मानवता और धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, के जीवन, शिक्षाओं और अनुपम शहादत के सम्मान में बड़े स्तर पर आयोजित समागमों के हिस्से के तौर पर करवाया गया। लाइट एंड साउंड शो के दौरान 'हिंद दी चादर' श्री गुरू तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन को डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया। इससे पहले ढाडी जत्थे दीदार सिंह संगतपुरा (फगवाड़ा) द्वारा वार का गायन किया गया। इस मौके पर पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत तथा पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली विशेष तौर पर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर भी इस मौके पर मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने लोगों से श्री गुरू तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की अपील की, जो 350 साल बाद भी समूची मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि श्री गुरू तेग बहादुर जी की अनुपम शहादत किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के मौलिक अधिकारों और सम्मान के लिए थी। श्री भगत ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी की अनुपम शहादत, सत्य के राह पर चलने के सिद्धांत और धार्मिक आजादी के संदेश को समूची मानवता तक पहुंचाने के लिए गुरू साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित समागमों की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में श्री गुरू तेग बहादुर जी के जीवन और अनुपम शहादत पर आधारित लाइट एंड साउंड शो करवाए जा रहे है, जिनकी शुरुआत आज जालंधर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट जिलों से हो गई है। इन समागमों की श्रृंखला के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चार नगर कीर्तन भी सजाए जा रहे है। एक नगर कीर्तन 19 नवंबर को गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) से सजाया जाएगा तथा शेष तीन नगर कीर्तन फरीदकोट, बठिंडा और गुरदासपुर से सजाए जाएंगे। चारों नगर कीर्तन 22 नवंबर की शाम को श्री आनंदपुर साहिब में पहुंचेंगे, जहां 23 से 25 नवंबर तक 350वें शहीदी पुरब को समर्पित समागम करवाए जाएंगे। उन्होंने संगतों से इन समागमों में बढ़–चढ़कर शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर से सजाया जाने वाला नगर कीर्तन 21 नवंबर को जालंधर में प्रवेश करेगा तथा यहां ठहराव के बाद श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना होगा। पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने कहा कि पंजाब सरकार यह यकीनी बना रही है कि गुरू साहिब जी के दर्शन और अनुपम शहादत के बारे में पंजाब और देश के हर कोने तक जानकारी पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ियां इस महान कुर्बानी से प्रेरणा और सीख ले सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक से लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति लोगों विशेषकर युवाओं को गुरू साहिब के शांति, सहिष्णुता और विश्वव्यापी भाईचारे को मजबूत करने के दर्शन से परिचित करवाने के साथ–साथ अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि श्री गुरू तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे समागम न केवल पंजाब के लिए बल्कि समूचे देश और मानवता के लिए हैं, जो कुर्बानी और मानवीय अधिकारों की रक्षा के प्रतीक के रूप में बहुत महत्व रखते है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा एक अनोखी पहल करते हुए हर जिले में पहुंचने पर नगर कीर्तन को शानदार 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक 350वें शहीदी पर्व को समर्पित समागम करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समागमों की शुरुआत 23 नवंबर को अखंड पाठ साहिब के साथ होगी, जिसके बाद सर्व धर्म सम्मेलन, विरासत–ए–खालसा में एक प्रदर्शनी, शाम 5 बजे श्री गुरू तेग बहादुर साहिब के जीवन और कुर्बानी को दर्शाता अपनी तरह का पहला ड्रोन शो तथा शाम 6 बजे कीर्तन दरबार होगा। दिन की समाप्ति 卐शहादत दी लो卐 के साथ होगी, जिसके तहत मशालें जला कर पवित्र शहर को रोशन किया जाएगा। 24 नवंबर को नगर कीर्तन 'सीस भेंट' श्री कीरतपुर साहिब से आरंभ हो कर श्री आनंदपुर साहिब आएगा। पंजाब विधान सभा द्वारा इतिहास में पहली बार श्री आनंदपुर साहिब में भाई जैता जी की यादगार पर विशेष सत्र करवाया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस सेशन में नौवें गुरू साहिब को श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। 25 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थों द्वारा 9वें पातशाह की बाणी का रसभिन्न कीर्तन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं की शिरकत वाला 卐सर्व धर्म सम्मेलन卐 भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब में विरासत–ए–खालसा में श्री गुरू तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत को दर्शाता 500 ड्रोनों वाला तीन दिवसीय (23 से 25 नवंबर) ड्रोन शो करवाया जाएगा। उत्तर भारत का यह पहला ड्रोन शो नौवें पातशाह को सुहृद श्रद्धांजलि होगी। संगत से इन समागमों में बढ़–चढ़कर शिरकत करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदी समागमों को पूरी मर्यादा और सुचारू ढंग से पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मेयर विनीत धीर, चेयरमैन पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक पवन कुमार टीनू, आप नेता राजविंदर कौर थियाड़ा, हलका विधायक करतारपुर बलकार सिंह की धर्म पत्नी हरप्रीत कौर तथा बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और संगत पहुंची हुई थी।

लोकमान्य तिलक-विचार और दर्शन का युग निर्माता

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा
ब्यूरो चीफ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले युगपुरुषों में बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है। उन्हें 卐लोकमान्य तिलक卐 इसीलिए कहा गया क्योंकि वे जनमानस के नेता थे उनकी विचारधारा ने भारत के आत्मसम्मान और आत्मबल को नई दिशा दी। उनके विचार और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और युवा पीढ़ी को कर्तव्य, राष्ट्रप्रेम और आत्मगौरव की प्रेरणा देते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता, पत्रकार, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 卐लोकमान्य卐 और 卐भारतीय अशांति के जनक卐 कहा गया। अंग्रेज उन्हें 卐भारतीय अशान्ति के पिता卐 कहते थे। उन्हें, 卐लोकमान्य卐 का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है 卐लोगों द्वारा स्वीकृत卐 उनके नायक के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें 卐आधुनिक भारत का निर्माता卐 कहा जाता है उनका जन्म 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी मे हुआ था। लोकमान्य तिलक का सबसे प्रसिद्ध और ओजस्वी नारा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा! इस विचार ने भारतीयों को पहली बार यह अहसास दिलाया कि स्वतंत्रता कोई याचना नहीं, बल्कि अधिकार है। तिलक मानते थे कि अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना कोई सामाजिक या शैक्षिक सुधार संभव नहीं है। उनका यह सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बन गया। तिलक की सबसे प्रसिद्ध रचना 'गीता रहस्य' है, जिसे उन्होंने मांडले जेल (बर्मा) में लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवद गीता की व्याख्या करते हुए कहा कि- संन्यास नहीं, कर्म ही सच्चा धर्म है। तिलक के अनुसार, गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और राष्ट्र सेवा का व्यावहारिक मार्गदर्शक है। वे मानते थे कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व निभाने चाहिए। बाल गंगाधर तिलक उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य न्याय के आधार पर नहीं, बल्कि शक्ति के बल पर चल रहा है। उन्होंने संघर्ष, असहयोग और जनजागरण को आज़ादी का सही मार्ग बताया। उनका मानना था कि केवल प्रार्थना और याचिकाओं से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती उसके लिए जनआंदोलन और बलिदान आवश्यक है। तिलक ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की वकालत की। उन्होंने ष्ठद्गष्ड्डठ्ठ श्वस्त्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ स्शष्द्बद्गह्ल4 और स्नद्गह्म्द्दह्वह्यह्यशठ्ठ ष्टशद्यद्यद्गद्दद्ग की स्थापना की। उनके अनुसार शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम होनी चाहिए। तिलक ने धर्म को कर्म, सेवा और राष्ट्रभक्ति से जोड़ा। उन्होंने गणेशोत्सव (1893) और शिवाजी जयंती (1895) जैसे पर्वों की शुरुआत की ताकि समाज में एकता और राष्ट्रीय चेतना का संचार हो। उनके लिए धर्म कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं था, बल्कि जनजागरण का शक्तिशाली माध्यम था। तिलक ने वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अद्धद्ग ह्रह्म्ष्ह्लद्बष् ॥शद्वद्ग द्बठ्ठ ह्लद्धद्ग क्कद्गस्त्रड्डह्य नामक पुस्तक में बताया कि आर्य लोग मूलतः आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना था, ताकि भारतीयों में अपनी परंपरा के प्रति सम्मान जागे।

बाल गंगाधर तिलक का सामाजिक दृष्टिकोण परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति पर आधारित था। वे मानते थे कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने पर ही संभव है। तिलक ने भारतीय समाज में जनजागरण फैलाने के लिए धर्म और परंपरा को माध्यम बनाया। उन्होंने गीता के कर्मयोग सिद्धांत को अपनाकर लोगों को कर्तव्यपरायणता और देशसेवा के लिए प्रेरित किया। सामाजिक सुधार के आधुनिक आंदोलनों के स्थान पर उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को प्राथमिकता दी। सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों के जरिए उन्होंने समाज में एकता, संगठन और राष्ट्रप्रेम की भावना को जगाया। महिला शिक्षा के वे समर्थक थे, किंतु उनकी सोच परंपरागत सीमाओं में ही थी। तिलक ने बाल विवाह या विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर प्रत्यक्ष सुधार की बात नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन भीतर से ही आना चाहिए, न कि पश्चिमी दबाव में। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे और उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। कुल मिलाकर तिलक का सामाजिक दृष्टिकोण राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान, परंपराओं की रक्षा और जनजागरण पर केंद्रित था, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार बना।इस प्रकार हम देखते है कि अपने आदर्शो के अनुसार जिसे सांचे में तिलक भारत को तब्दील करने का कार्य कर रहा थे पर जिसे समय के कारण पूरा न कर सका था जिस को बाद में महात्मा गांधी जी ने पूरा किया था तिलक भारत के लिए कार्य कर रहे थे जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस कर रहा था कि यह मेरा देश है इस के लिए मैं आप कार्य करोगा इस प्रकार का भारत जिसमें सारी जातियों के लोग आपस में प्रेम और भाईचारा रखे गए।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

ज्योतिसर अनुभव केन्द्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पंचजन्य स्मारक -सुभाष सुधा

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक – हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गीता स्थली ज्योतिसर को विश्व का एक सुंदर पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास किए है और करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिसर अनुभव केन्द्र तैयार किया है। इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र के परिसर में अब भव्य पंचजन्य स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक पर भव्य शंख स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को इस पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन भी कर सकते है। हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा मंगलवार को ज्योतिसर अनुभव केंद्र में केडीबी व प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पंचजन्य स्मारक के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पूर्व राज्यमंत्री ने कहा कि इस पंचजन्य स्मारक का निर्माण ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बाहर परिसर में किया जाएगा। इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है और

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर सकते है पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन, पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने पंचजन्य स्मारक के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

इस डिजाइन के अनुसार इस पर एक भव्य शंख भी स्थापित किया जाएगा। इस स्मारक को भव्य और सुंदर बनाया जाएगा ताकि विश्व के कोने–कोने से आने वाले पर्यटक ज्योतिसर अनुभव केन्द्र में प्रवेश करने से पहले इस भव्य स्मारक के दर्शन कर सके। न्होंने कहा कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर अनुभव केंद्र का अवलोकन भी कर सकते है। इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र में पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही है। इतना ही नहीं अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का अवलोकन कर तैयारियों का जायजा लिया था। यह वह धरा है जहां पर हजारों साल पहले भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया और पूरी मानवता जाति के कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए। इस लिए इस तीर्थ व पर्यटन स्थल को केन्द्र व प्रदेश सरकार की तरफ से भव्य व सुंदर बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में विश्व से आने वाले लोग इस तीर्थ स्थल के दर्शन कर सके। इस मौके पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, एएसपी प्रतीक गहलोत, डीएमसी अमन कुमार, सीईओ जिला परिषद शम्भू राठी, एसडीएम अभिनव सिवाच,केडीबी के मानद सचिव उपेन्द्र सिंघल, सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण शर्मा आदि उपस्थित थे।

आदेश में श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व

मेडिकल स्टूडेंटस व स्टॉफ ने किया रक्तदान

एस. के. सक्सैना

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक – आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मोहड़ी में सिखों के प्रथम गुरु धन–धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान आदेश परिसर गुरबाणी के वातावरण से गूंज उठा। आदेश के प्रबंध निदेशक डा. गुणतास सिंह गिल ने बताया कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को मेडिकल कॉलेज कांप्लेक्स में श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया गया था, जिसका भोग 4 नवंबर को सुबह बड़ी श्रद्धा के साथ डाला गया। भोग उपरांत मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में कीर्तन दरबार सजाए गये। जिसमें प्रसिद्ध रागी भाई जोगिन्द्र सिंह रियार (लुधियाना) वालों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित किया। पूरे पंडाल में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह के जयकारे गूंज उठे। इस दौरान हजारों की संख्या में मेडिकल छात्र– छात्राओं, स्टाफ सदस्यों और संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के

समक्ष शीश नवाया और अरदास कर गुरू घर की कृपा प्राप्त की। इस अवसर पर आदेश ग्रुप के चेयरमैन डा. एच.एस. गिल, आदेश ग्रुप की महासचिव कमलदीप कौर, आदेश ग्रुप के प्रबंध निदेशक गुर फतेह सिंह गिल, आदेश यूनिवर्सिटी भठिंडा के प्रबंध निदेशक डा. गुरप्रीत सिंह गिल, आदेश मेडिकल कॉलेज मोहड़ी के प्रबंध निदेशक डा. गुणतास सिंह गिल ने संगत को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई दी। इस दौरान डा. एच.एस. गिल ने मेडिकल स्टूडेंटस को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का मार्ग केवल मेहनत और सेवा भाव से ही बनता है। चिकित्सा एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। आदेश परिवार को चाहिए कि हर मरीज की देखभाल को ईश्वर सेवा समझकर करें। तत्श्चात लंगर सेवा में सभी ने श्रद्दा के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण किया।

प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित–श्रीगुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। जिसमें उत्साह के साथ स्टूडेंटस व स्टॉफ ने रक्तदान किया। समाचार लिखे जाने तक रक्तदान शिविर में 55 यूनिट रक्त यूनिट डोनेट हुई थी। आदेश में मनाये गये प्रकाश पर्व के दौरान लंगर प्रसाद ग्रहण करते संगत।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'म्हारी सड़क ऐप की शिकायतों पर लिया संज्ञान, 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई के दिए निर्देश

पंकज

चण्डीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 'म्हारी सड़क ऐप% की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के सम्बंधित 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इनमें पीडब्ल्यूडी के 2, एचएसएएमबी के 6, एसएसआईआईडीसी के 2, जिला परिषद का 1, यूएलबी के 5 और एसएसवीपी के 3 कार्यकारी अभियंता शामिल है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए कि जो ठेकेदार तैय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, संबंधित विभाग उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां 'म्हारी सड़क ऐप' पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य दिया जाता है या लोगों की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान धरातल पर शत प्रतिशत दिखना चाहिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी गई सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करे, यदि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त

शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर लिया एक्शन

कार्रवाई करे। साथ ही, प्रदेश की सड़कों पर सफेद पट्टी व साइन बोर्ड लगवाने भी सुनिश्चित किए जाए। म्हारी सडक ऐप पर शिकायत आते ही अधिकारी तय समय सीमा में करे समाधान श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि म्हारी सड़क एप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पडें। यदि कोई सम्बंधित अधिकारी शिकायत का समय पर समाधान नहीं करता या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ सम्बंधित विभाग सख्त कार्यवाही करे।

म्हारी सड़क ऐप की जानकारी को लेकर लोगों को किया जाए जागरूक

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि म्हारी सड़क ऐप की जानकारी और डाउनलोड करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से जागरूक करे, ताकि सड़क से सम्बंधित समस्या को लेकर वें ऐप को उपयोग कर सकें। इसके अलावा, सडकों के गड्ढों को ठीक प्रकार से भरा जाए, इसको लेकर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

अधिकारी सड़कों की मैपिंग का कार्य जल्द करे पूरा

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि छोटी व बड़ी शिकायतों का अलग–अलग वर्गीकरण कर तय समय सीमा में निस्तारण करना भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऐप पर जो नागरिक गड्ढों की फोटो डालकर जानकारी देता है तो उससे बात करना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंनें ऐप के सम्बंध में फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देने के निर्देश दिए है ताकि उन्हें ऐप के संचालन की सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा, जिस विभाग की सड़कों की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई वे मैपिंग का कार्य भी जल्द करे। इससे भविष्य में उस सड़क पर कार्य करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त, ऐप पर एक सेल अलग से बनाकर एनएच की सडकों की शिकायतों को उस पर डाला जाए।

इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी भाषा ओलंपियाड के लिए दुनिया भर से 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने करवाई पंजीकरण- हरजोत बैंस

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे आकर्षक इनाम और विशेष पुरस्कार, शीर्ष स्कूलों को भी मिलेगा सम्मान–शिक्षा मंत्री

मनदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी एस ई बी) द्वारा आयोजित किए जा रहे तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी भाषा ओलंपियाड में विद्यार्थियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए अब तक 2,25,916 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि यह उत्साह विश्व स्तर पर पंजाबी भाषा के बढ़ते प्रसार और स्वीकार्यता का स्पष्ट प्रमाण है। इस वर्ष का आंकड़ा पिछले संस्करणों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है–जहां क्रमशः 24,698 और 6,689 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। स बैंस ने कहा कि लगभग नौ गुना बढ़ोतरी युवा पीढ़ी में पंजाबी भाषा के प्रति बढ़ती रुचि और उत्साह का द्योतक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के

सतत प्रयासों को इसका श्रेय देते हुए स बैंस ने कहा कि दुनियाभर में 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपनी भाषाई जड़ों से जुड़ते देखना हमारे लिए एक सपना साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी हमारी उस व्यापक और लक्षित रणनीति की सफलता है, जो वैश्विक स्तर पर पंजाबी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु बनाई गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक श्रेणी (प्राथमिक, मिडल और सेकेंडरी) में पहले 10 विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार निर्धारित किए हैं–पहला पुरस्कार 11,000 रुपए, दूसरा 7,100 रुपए और तीसरा 5,100 रुपए। इसके अतिरिक्त, संस्थागत स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने हेतु श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को भी विशेष सम्मान और मान्यता दी जाएगी। स बैंस ने कहा कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय पंजाबी भाषा ओलंपियाड केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारी पहचान, मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल भाषा कौशल की परीक्षा नहीं, बल्कि पंजाबी भाषा और संस्कृति के भविष्य के संवाहकों को तैयार करने का एक प्रयास है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ दीं।

नक्शा-विश्वसनीय भू-अभिलेखों और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल

माननीय शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

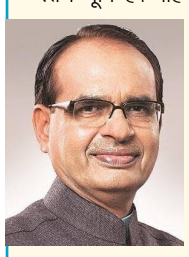

जब भारत एक समावेशी और विकसित भविष्य की कल्पना करता है, तो इसका सबसे मज़बूत आधार–स्तंभ भूमि है। चाहे घर हो, खेत हो, दुकान हो या स्मार्ट सिटी का सपना हो – विकास का प्रत्येक रूप भूमि पर अवस्थित होता है। हालाँकि, सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू–अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, ज़मीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इन दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने 卐नक्शा卐 (राष्टीय शहरी निवास–स्थल भू–स्थानिक ज्ञान–आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि–रिकॉर्ड रख–रखाव में बदलाव लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू–अभिलेख प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कस्बों और शहरों के विकास को भी गति प्रदान करेगी।

भारत में, भूमि पंजीकरण लंबे समय से एक जटिल व दस्तावेज–आधारित प्रक्रिया रही है। बिक्री विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पटवारी सत्यापन और तहसील स्तर पर प्रस्तुतियाँ ङ्क ये सभी नागरिकों के लिए पूरी प्रणाली को बोझिल बना देती थीं। पुराने रजिस्टर और फाइलों में न केवल त्रुटियां मौजूद थीं, बल्कि इनमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी, जो कई विवादों का मूल कारण होता है। अस्पष्ट संपत्ति अभिलेखों की वजह से बैंकों से ऋण प्राप्त करने की संभावना कम हो गयी थी। उत्तराधिकार या दाखिल–खारिज की प्रक्रिया अक्सर वर्षों तक अदालतों में अटकी रहती थी। गलत माप, अस्पष्ट सीमाएँ और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। यही कारण है कि लाखों भारतीयों के लिए, सुरक्षा के स्रोत के रूप में भूमि का महत्त्व कम होता गया और यह जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गई।

नक्शा डिजिटल पारदर्शिता की ओर कदम–नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू–रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। इस पहल के तहत, नागरिकों को 'योरप्रो'

(शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड) कार्ड मिलता है, जो स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण है और संपत्ति के लेन–देन को आसान बनाता है। सरकार 'योरप्रो' कार्यक्रम को समर्थन दे रही है। नक्शा के साथ, लोगों को अब स्वामित्व की पुष्टि के लिए दस्तावेजों या बिचौलियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऋण प्राप्त करने, बिक्री पूरी करने, उत्तराधिकार प्राप्त करने और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया तेज़ और अधिक पारदर्शी हो गयी है। अंततः, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है – यह नागरिक सशक्तिकरण, समानता और भू–स्वामित्व में कानूनी आश्वासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नक्शा कार्यक्रम मुख्य रूप से उन नागरिकों को लाभान्वित करता है, जो लंबे समय से अधूरे या अप्रचलित भू–दस्तावेजों पर निर्भर रहे हैं। नगरपालिकाओं और स्थानीय परिषदों के पास अब स्वच्छ, सटीक भू–स्थानिक डेटा तक पहुँच की सुविधा है, जिससे बेहतर निर्णय लेना और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। नागरिक आसानी से ऑनलाइन प्रारूप मानचित्र देख सकते हैं और आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह डिजिटल प्रणाली कराधान को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है, साथ ही शहरी नीति–निर्माण और अवसंरचना डिज़ाइन की सटीकता और गति में सुधार करती है। संक्षेप में, जो भू–रिकॉर्ड कभी धूल भरे रजिस्टरों में केवल हस्तलिखित प्रविष्टियों के रूप में मौजूद था, वह अब रंगीन, इंटरैक्टिव और पारदर्शी डिजिटल मानचित्रों में विकसित हो गया है। यह आधुनिक, डेटा–संचालित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नक्शा कार्यक्रम का प्रभाव व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह आपदा प्रबंधन और शहरी नीति–निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। अवस्थिति की ऊँचाई का विस्तृत डेटा प्रदान करके, यह लोगों को बाढ़–जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि चक्रवात, भूकंप या आग की स्थिति में, यह बिना किसी देरी के बचाव और राहत कार्यों को शुरू करने की सुविधा देता है। सत्यापित डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड यह भी सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा और सहायता सही लाभार्थियों तक शीघ्रता से

नक्शा आपकी भूमि की डिजिटल पहचान का प्रतीक

पहुँचे। इससे आपदा के बाद, पूर्वस्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। इसके अलावा, नक्शा संतुलित और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शहरी सुदढ़ता का समर्थन करता है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और दिव्यांगजनों जैसे कमजोर समूहों के लिए, नक्शा सुरक्षा और सुलभता प्रदान करता है–उन्हें संपत्ति के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और सत्यापित करने की सुविधा देता है, किसी भी धोखाधड़ी और अतिक्रमण के जोखिम को कम करता है, और सरकारी कार्यालयों के बार–बार चक्कर लगाए बिना आसान पहुँच सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि दुनिया भर के उन नागरिकों के लिए विश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिनकी भारत की भूमि और इसके भविष्य में हिस्सेदारी है।

विकसित भारत की आधारशिला

भारतीय इतिहास में, भूमि विवादों ने अक्सर असमानता, संघर्ष और विलंब को जन्म दिया है– लेकिन नक्शा कार्यक्रम भूमि प्रशासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और नागरिक–केंद्रित बनाकर इस विरासत को बदल रहा है। स्मार्ट शहर, पीएम गति शक्ति और पीएम स्वनिधि जैसे राष्टीय मिशनों के साथ एकीकरण के जरिये, नक्शा भारत के विकास–केंद्रित भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। यह न केवल स्थानीय शासन को मज़बूत करता है, बल्कि नागरिक भागीदारी, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे अधिक निवेश और रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है। आख़िरकार, भूमि सिर्फ़ एक भौतिक संपत्ति नहीं है–यह प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान और विरासत है। दशकों से, यह विरासत अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आवरण से ढँकी हुई थी, लेकिन नक्शा विश्वास, पारदर्शिता और समानता का अमृत काल प्रस्तुत कर रहा है। सुरक्षित, सत्यापित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ, अब नागरिकों के पास सचमुच अपने सपनों की कुंजी है–जो भारत को एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकसित भविष्य की ओर ले जा रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान भाई-बहनों को 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार' प्रदान किए

पीपीवीएफआरए अधिनियम की रजत जयंती और प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस पर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ

रमन कुमार

नई दिल्ली–केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित सी. सुब्रमण्यम सभागार में 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और पीपीवीएफआरए अधिनियम, 2001 के रजत जयंती व पीपीवीएफआरए (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण) के 21वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भागीदारी की और चयनिय किसान भाई–बहनों को पुरस्कृत किया।

इस अवसर केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के कम्यूनिटि सीड बैंक, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल के शिक्षा निकेतन, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, असम के सीआरएस–एनए दिहिंग तेंगा उन्नयन समिति, उत्तराखंड के श्री भूपेंद्र जोशी, केरल के श्री टी. जोसेफ, श्री लक्षण प्रमाणिक, श्री अनंतमूर्ति जे, बिहार के श्री नकुल सिंह, उत्तराखंड के श्री नरेंद्र सिंह सहित विभिन्न अन्य श्रेणियों में किसान भाई–बहनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि पीपीवीएफआरए प्राधिकरण ने पिछले 20 वर्षों में अद्भुत काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि पद्धति अत्यंत प्राचीन है। कृषि हमारे देश का मूल रहा है। अनेक बीजों की किस्में पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बीते वर्षों में कुछ किस्में विलुप्त होने की कगार पर आ गई थीं, जिन्हें सहेजने में किसान भाई–बहनों ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के माध्यम से बीज संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपये तक की धनराशि देने का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि बीज सबसे बड़ी पूंजी है। बीज हमारा मौलिक अधिकार है। नई किस्मों को बढ़ावा देना जरूरी लेकिन पुरानी किस्मों को भी बचाना है, दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करने के प्रस्ताव की भी चर्चा की और कहा कि जहां आवश्यक होगा वहां अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा। आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम के बारे में अभी भी किसानों को कम जानकारी है पंजीकरण को लेकर भी कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। पारदर्शिता के स्तर पर भी कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों तक अधिनियम का वास्तविक लाभ का हिस्सा भी सीमित रूप से ही पहुंच पाता है जिस दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम का अन्य कानूनों के साथ समन्वय और वैज्ञानिक डेटाबेस को मजबूत करने की भी बात कही। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक दृष्टि से किसानों के द्वारा पौधों और बीजों की किस्मों को संरक्षित करने के उपायों की चर्चा की और बताया कि इसी संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए पीपीवीएफआरए के माध्यम से कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सशक्त प्रणाली पौधों और बीजों के संरक्षण में और अधिक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए किसान कल्याण में नए अध्याय जोड़ेगी। कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने मडुआ जैसी विभिन्न प्रजातियों के बीजों के संरक्षण पर बल देते हुए संगठन से इस दिशा में और सक्रिय प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने मडुआ के समान अन्य पौधों की प्रजातियों के औषधीय महत्व को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, पीपीवीएफआरए के रजिस्ट्रार–जनरल डॉ. डी. के. अग्रवाल उपस्थित रहे।

पंजाब के राज्यपाल ने श्री देवी तलाब मंदिर में पवित्र सरोवर की कार सेवा का किया शुभारंभ

लोगों से सेवा में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने की अपील

एस. के. सक्सैना

जालंधर, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर जालंधर में सरोवर की कार सेवा की शुरुआत की और सभी वर्गों के लोगों को न्योता देते हुए इस पवित्र सेवा में सक्रिय तौर पर भाग लेने की अपील की। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुंडियां, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, पद्म भूषण बरजिंदर सिंह हमदर्द और श्री देवी तलाब प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री शीतल विज के साथ पंजाब के राज्यपाल कार सेवा की शुरुआत करने से पहले पवित्र मंदिर में नतमस्तक हुए। इस मौके पर संगत को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इस पवित्र सेवा में शामिल

होने पर धन्यवाद प्रकट करते हुए इसकी तुलना अपने घर की सफाई से की। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घरों को साफ–सुथरा रखते है, उसी तरह हमारा सबका कर्त्तव्य बनता है कि हम परमात्मा के घरों को भी इस कार सेवा के माध्यम से साफ रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठकर हर कोई मानवता और आध्यात्मिक संस्थाओं की निस्वार्थ सेवा करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थान हम सबको अपने कर्तव्य पूरे उत्साह से निभाने के लिए ताकत और आशीर्वाद प्रदान करते है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों को इस पवित्र सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे पहले प्रधान शीतल विज द्वारा विभिन्न गणमान्य का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा इस पवित्र कार्य में बहुमूल्य योगदान देने वाली का सम्मान किया गया। इस मौके पर मेयर विनीत धीर, सीनियर आप नेता नितिन कोहली, राजविंदर कौर थियाडा और दिनेश ढल्ल भी मौजूद थे।

दयालु योजना का लाभ ओर अधिक तेजी व सटीकता से मिलेगा- मुख्यमंत्री

दयालु–II योजना पोर्टल का किया शुभारम्भ

मनदीप कौर

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दयालु योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए दयालु–द्वद्व योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री आज चण्डीगढ में दयालु–द्वद्व योजना पोर्टल का शुभारम्भ कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, प्रधान सचिव पर्यटन श्रीमति कला रामचन्द्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु –द्वद्व पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ ओर अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके किसी सदस्य की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। जबकि चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक http://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाईल एप के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा 'वंदे मातरम' स्वतंत्रता का गीत, अटूट संकल्प की भावना और भारत के जागरण का प्रथम मंत्र है

'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर एक ब्लॉग में श्री अमित शाह ने कहा 'वन्दे मातरम' केवल भारत का राष्ट्रीय गीत और स्वतंत्रता आन्दोलन का प्राण ही नहीं, बल्कि 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की प्रथम उद्घोषणा है, औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया, 'वंदे मातरम' जागृति का प्रभात–गीत बन गया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'वंदे मातरम' गीत के इस इतिहास की देशवासियों को फिर से याद दिलाई, 'वंदे मातरम' आज भी विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प में प्रेरणा दे रहा है, अब, इस भावना को आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत में परिवर्तित करना हमारी ज़िम्मेदारी

नई दिल्ली (एस. के. सक्सैना)– केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर अपने एक ब्लॉग में कहा कि वन्दे मातरम' केवल भारत का राष्ट्रीय गीत ही नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता आन्दोलन का प्राण ही नहीं बल्कि 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की प्रथम उद्घोषणा है। अपने लेख में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई अहम पड़ाव आए, जब गीतों, कलाओं ने अलग–अलग रूपों में लोकभावनाओं को सहेजकर आंदोलन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना के युद्धगीत हों, आज़ादी के आंदोलन में सेनानियों के गान या आपातकाल के विरुद्ध युवाओं के सामूहिक गीत, गीतों ने भारतीय समाज को स्वाभिमान की प्रेरणा भी दी और एकजुट भी बनाया। ऐसा ही है भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम', जिसका इतिहास किसी युद्धभूमि से नहीं,बल्कि एक विद्वान बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी के शांत लेकिन अडिग संकल्प से शुरू होता है। सन् 1875 में, जगद्धात्री पूजा (कार्तिक शुक्ल नवमी या अक्षय नवमी) के दिन, उन्होंने उस स्तोत्र की रचना की जो भारत की स्वतंत्रता का शाश्वत गीत बन गया। 'वन्दे मातरम' केवल भारत का राष्ट्रीय गीत ही नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता आन्दोलन का प्राण ही नहीं बल्कि यह बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय जी द्वारा 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की प्रथम उद्घोषणा है। इसने हमें याद दिलाया कि भारत केवल ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भू–सांस्कृतिक राष्ट्र है – जिसकी एकता उसकी संस्कृति और सभ्यता से आती है। जैसा कि महर्षि अरबिंद ने वर्णन किया, बंकिम आधुनिक भारत के एक ऋषि थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित किया। अपने एक पत्र में, बंकिम बाबू ने लिखा॰ 卐मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि मेरे सभी कार्य गंगा में बहा दिए जाएँ। यह श्लोक ही अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा।卐 औपनिवेशिक भारत के सबसे अंधकारमय काल में लिखा गया, 'वंदे मातरम' जागृति का प्रभात–गीत बन गया। 1896 में, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने 'वंदे मातरम' को धुन में पिरोया, जिससे इसे वाणी और अमरता प्राप्त हुई। यह गीत भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंज उठा। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने इसका तमिल अनुवाद किया और पंजाब में क्रांतिकारियों ने इसे गाते हुए ब्रिटिश राज को खुली चुनौती दी। 1905 में, बंग–भंग आंदोलन के दौरान 'वंदेमातरम' के सार्वजनिक पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी, 14 अप्रैल, 1906 को बारीसाल में, हजारों लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की। जब पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर लाठीचार्ज किया, तो पुरुष और महिलाएँ सड़कों पर 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए लहूलुहान हो गए। वहाँ से, 'वंदे मातरम' का मंत्र, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ कैलिफ़ोर्निया पहुँच गया, आज़ाद हिंद फ़ौज में गूँजा, जब नेताजी के सैनिक सिंगापुर से मार्च कर रहे थे और 1946 के रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूँजा, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। खुदीराम बोस से लेकर अशफ़ाक़उल्ला ख़ान तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तिरुपुर कुमारन तक, नारा एक ही था। यह अब सिर्फ़ एक गीत नहीं रहा; यह भारत की सामूहिक आत्मा की आवाज़ बन गया था। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था, 'वंदे मातरम' में 卐सबसे सुस्त रक्त को भी जगाने की जादुई शक्ति卐 थी। महर्षि अरबिंद जी ने इसीलिए कहा था कि, यह 卐भारत के पुनर्जन्म का मंत्र卐 है। 26 अक्टूबर को 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'वंदे मातरम' गीत के इस इतिहास की देशवासियों को फिर से याद दिलाई और राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से भारत सरकार की ओर से अगले एक वर्ष तक अलग–अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया। इन आयोजनों के माध्यम से देश भर में 'वंदे मातरम' का पूर्ण गान होगा, जिससे देश की युवा पीढ़ी 'सांस्कृतिकराष्ट्रवाद' के विचार को आत्मसात कर पाए। आज जब हम भारत पर्व मना रहे हैं और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी याद करते हैं कि कैसे सरदार साहब ने 'एक भारत' का निर्माण कर 'वंदे मातरम' की भावना को ही मूर्त रूप दिया 'वंदे मातरम' आज भी विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प में प्रेरणा दे रहा है। अब, इस भावना को आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत में परिवर्तित करना हमारी ज़िम्मेदारी है। वंदे मातरम' स्वतंत्रता का गीत है, अटूट संकल्प की भावना है, और भारत के जागरण का प्रथम मंत्र है। राष्ट्र की आत्मा से जन्मे शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वे सदैव जीवित रहते हैं, पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं को भारतीयता की दृष्टि से देखें।

रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना (25.72 कि.मी.) को मंजूरी दी- रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री

रेलवे ने पंजाब के मुख्य सचिव को भूमि के शीघ्र अधिग्रहण हेतु पत्र लिखा, परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को लाभ होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़ – रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। यह परियोजना कुल 25.72 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत ?764.19 करोड़ है, जिसमें से ?166 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित हैं, जो रेलवे द्वारा वहन किए जाएंगे। आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि जम्मू–फिरोजपुर–फाजिल्का–मुंबई कॉरिडोर की दूरी 236 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह परियोजना मालवा और माझा क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, और रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करते हुए बिट्टू ने कहा कि यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपहार है।

नई रेल लाइन जालंधर–फिरोजपुर और पट्टी–खेमकरण मार्गों को जोड़ेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट एक सीधा और वैकल्पिक संपर्क स्थापित होगा। यह मार्ग रणनीतिक रक्षा महत्व वाले क्षेत्रों से होकर गुज़रेगा, जिससे सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित होगी। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक फायदे होंगे। इससे लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह रेल लाइन प्रतिदिन 2,500 से 3,500 यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करेगी, जिससे विशेष रूप से छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण मरीजों को लाभ पहुंचेगा। यह रेल लिंक व्यापार और औद्योगिक विकास को गति देगा, माल परिवहन लागत को कम करेगा तथा कृषि बाजारों तक पहुंच आसान बनाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नई रेल लाइन अमृतसर, जो एक प्रमुख व्यावसायिक, शैक्षणिक और धार्मिक केंद्र है और जहां प्रतिदिन एक लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, को फिरोजपुर से तेज़ और मजबूत संपर्क प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नया मार्ग विभाजन के समय खोए हुए ऐतिहासिक रूट को पुनर्जीवित करेगा, जिससे फिरोजपुर–खेमकरण की दूरी 294 किलोमीटर से घटकर 110 किलोमीटर रह जाएगी। डीआरएम अंबाला श्री विनोद भाटिया, सीपीएम/निर्माण श्री अजय वार्ष्णेय, सीपीएम/आरएलडीए श्री बलबीर सिंह, एडीआरएम फिरोजपुर श्री नितिन गर्ग एवं श्री धनंजय सिंह, ईडीपीजी/रेल राज्यमंत्री भी वहां मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा प्रदेश को देंगे कई नई परियोजनाओं की सौगात -सुमन सैनी

लाडवा, प्रमोद कौशिक – हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ किया है। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में श्री गुरुतेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश को कई नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव खानपुर कौलिया, गांव बीड मथाना, गांव सिरसमा व पिपली में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को 25 नवंबर को ज्योतिसर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का न्यौता दिया। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि लाडवा क्षेत्र में सड़कों के सौंदर्यकरण व सुदृढ़करण, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मौजूदा समय में लाडवा विधानसभा के सभी गांवों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। लाडवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में विकास कार्यों पर 807 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 310 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आगामी समय में और भी योजनाएं लाडवा विधानसभा के लोगों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। जो पात्र महिलाएं अभी इस योजना से वंचित

उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने लाडवा विधानसभा के गांव खानपुर कौलिया, गांव बीड मथाना, गांव सिरसमा व पिपली के नागरिकों को दिया कार्यक्रम का न्योता

हैं, वो महिलाएं पोर्टल या अपने मोबाइल फोन से आवेदन करें।

11.51 करोड़ रुपये की लागत से 65 गांवों में बिछाई गई पीने के पानी की पाइप लाइन–उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि लाडवा विधानसभा के 65 गांवों में पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम 11 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से किया गया है। लाडवा शहर में सहारनपुर– कुरुक्षेत्र सड़क को चार–मार्गी करने का काम 10 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से किया गया है। इसी तरह गांव बहलोलपुर में 8 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से आईटीआई का निर्माण किया गया। गांव कनीपला में 5 करोड़ रुपए की लागत से 33 के.वी. पावर सब–स्टेशन स्थापित किया गया है।

बिहोली गांव में 4.24 करोड़ से स्थापित की गई पशु वेटनरी पॉलीक्लीनिक–उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि गांव बिहोली में पशु वेटनरी पॉलीक्लीनिक का निर्माण 4 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसमें आधुनिक मशीनें स्थापित की गई। इस वेटनरी पॉलीक्लीनिक से पशुओं के एक्स–रे, रक्त जांच और आधुनिक मशीनों से अन्य प्रकार की जांच जाएगी। इसी तरह लाडवा में 26 करोड़ रुपये की लागत से मल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया और सीवरेज लाइन बिछाई गई।

लाडवा की 9240 महिलाओं को 500 रुपये में मिल रहे गैस सिलेंडर–उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि हर घर गृहिणी योजना में 9 हजार 240 परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 364 मकानों का निर्माण किया गया है और 249 मकान निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के गांव उमरी में उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना 108 करोड़ रुपये की लागत से की गई है। गांव उमरी में ही 14 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से सरकारी पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण किया गया।

कार्यक्रम ये रहे मौजूद–इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, चेयरमैन जसविंदर जस्सी, महिला जिलाध्यक्ष वंदना गौरी, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, परमजीत कौर कश्यप, सुरेंद्र माजरी, सरपंच रामकुमार खानपुर कौलिया, सरपंच नरेंद्र नैन बीड मथाना, सरपंच देवीदयाल सिरसमा, गुरुदत्त शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 नवाचार और समावेशिता का प्रतीक होगा, महिला फिल्म निर्माताओं, नई प्रतिभाओं और सिनेमा में रचनात्मक उत्कृष्टता का जश्न मनाएगा-केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन

नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम के साथ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की उल्टी गिनती शुरू, 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में 20 से 28 नवंबर, 2025 तक आयोजन, सिनेमा में 50 गौरवशाली वर्ष पूरे करने पर 56वें आईएफएफआई के समापन समारोह में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा, 81 देशों की 240 से अधिक फिल्मों में 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर शामिल, 5 महाद्वीपों की 32 फिल्मों में तीन उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, 2025 के विश्व के शीर्ष फिल्म समारोहों की शीर्ष पुरस्कार विजेता फिल्में पहली बार भारत में प्रदर्शित होंगी, 9 चयनित खंड- डॉक्यू–मोंटेज, फ्रोम द फेस्टिवल्स, राइजिंग स्टार्स, मिशन लाइफ, एक्सपेरीमेंटल फिल्म्स, रिस्टोर्ड क्लासिक्स, मैकाब्रे ड्रीम्स, यूनिसेफ और सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री फोकस- जापान, जापानी सिनेमा के चयनित पैकेज, संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, स्पेशल फिल्म पैकेज– साझेदार देश स्पेन और स्पॉटलाइट ऑस्ट्रेलिया, आईएफएफआई 2025 शताब्दी वर्ष मनाएगा और पुनर्स्थापित क्लासिक फिल्मों के माध्यम से दिग्गज फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को सम्मानित करेगा

नई दिल्ली (एस. के. सक्सैना)–56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 20 से 28 नवंबर, 2025 तक गोवा में आयोजित होगा। आईएफएफआई का कर्टन रेजर कार्यक्रम आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 4 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर जैसे एक व्यापक और विविध कार्यक्रम शामिल है। इस महोत्सव को 127 देशों से रिकॉर्ड 2,314 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो ग्लोबल फेस्टिवल सर्किट में आईएफएफआई की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष का आईएफएफआई कई नई पहलों की शुरुआत कर रहा है जो नवाचार और समावेशिता को दर्शाती हैं। डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि इस वर्ष 50 से अधिक महिला निर्देशकों की फ़िल्में प्रदर्शित हुई हैं, जो सिनेमा में

नारी शक्ति को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वेब और स्ट्रीमिंग सामग्री में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए इस वर्ष भी ओटीटी पुरस्कार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव पटकथा लेखन, प्रोडक्शन डिजाइन और ध्वनि जैसे क्षेत्रों में नई और उभरती प्रतिभाओं को निरंतर समर्थन प्रदान करता रहेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एंटी–पायरेसी कानूनों को मजबूत करने और फिल्म प्रमाणन को सरल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि बहुभाषी फिल्मों के लिए सीबीएफसी का आगामी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' प्रमाणपत्र भारत की सांस्कृतिक एकता को और बढ़ावा देगा।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

जनजातीय गौरव दिवस - भारत की जनजातीय विरासत और वीरों का उत्सव

लेखक – श्री सी. पी. राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति

भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार देने में जनजातीय समुदायों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास साक्षी है कि जनजातीय नेताओं ने अपने भूमि, संस्कृति और गरिमा की रक्षा के लिए, औपनिवेशिक शोषण और अन्याय के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलनों का नेतृत्व किया। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक, भारत में विभिन्न जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, स्थानीय जमींदारों और महाजनों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने उनके पारंपरिक जीवन–प्रणाली को बाधित किया था।

भगवान बिरसा मुंडा द्वारा संचालित उलगुलान आंदोलन से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, वीर गुंडाधुर, रानी गाइदिनल्यू, रामजी गोंड, शहीद वीर नारायण सिंह, सिद्धू–कान्हू जैसे वीरों के प्रखर प्रतिरोध तक — यह सिद्ध करता है कि जनजातीय आंदोलन केवल अलग–अलग संग्राम नहीं थे; बल्कि ये औपनिवेशिक अत्याचार के विरुद्ध सशक्त, निरंतर और संगठित प्रतिप्रवाह थे। उनके संघर्षों ने न केवल जनजातीय अधिकारों की रक्षा की, बल्कि स्वतंत्रता और समानता के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष को भी सुदृढ़ किया।

सन 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसके तहत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती (15 नवम्बर) को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ताकि इन जनजातीय नेताओं और उनके संघर्षों को सम्मान दिया जा सके। यह निर्णय एक युगांतरकारी कदम था, जिसने आने वाली पीढ़ियों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवशाली विरासत और उनके संघर्षों के प्रति गर्व और जागरूकता को स्थापित किया जा सकें।

इस वर्ष का उत्सव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज हम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती (जनजातीय गौरव वर्ष) के समापन का समारोह मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी।

मेरा अनुभव

मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा के दौरान संसद सदस्य रहा, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी देश के माननीय प्रधानमंत्री थे। अटलजी के कार्यकाल के दौरान ही जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी। लोकसभा सदस्य के रूप में, मैंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को अलग–अलग राज्यों के रूप में गठित करने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। बाद में मुझे झारखंड राज्य का राज्यपाल बनने का सौभाग्य मिला।

राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात, उसी दिन मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातु गया, जहाँ जाकर मैंने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे स्मरण है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी उलिहातु जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका यह दौरा मात्र एक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय तीर्थयात्रा के समान था, जिसने जनजातीय समाज के महत्व को पूरे राष्ट्र के समक्ष स्थापित किया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ खूँटी (झारखंड) में भी उपस्थित था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (क्क्रू–छ्वह्रू) योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कम?ार जनजातीय समुदायों की सुरक्षा और सशक्तिकरण करना है।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना की प्रेरणा का श्रेय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी को दिया, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जनजातीय समाज के उत्थान हेतु समर्पित किया है।

कल्याण से सशक्तिकरण की ओर- एक परिवर्तनकारी पहल

मैंने देखा है कि पिछले एक दशक में जनजातीय समुदायों के लिए नीतिनिर्माण के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है — जो पहले केवल कल्याण उन्मुख था, वह अब सशक्तिकरण उन्मुख बन गया है।

वर्ष 2023 में प्रारंभ किए गए PM-JANMAN मिशन ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह योजना 75 विशेष रूप से कम?ार जनजातीय समूहों को लक्षित करती है, और इसमें 9 मंत्रालयों की समन्वित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनका उद्देश्य 11 प्रमुख हस्तक्षेपों के माध्यम से इन समुदायों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है — जिनमें पक्के घर, सड़क, पेयजल, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ तथा वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करना शामिल है।

यह मिशन तीन वित्तीय वर्षों (2023–2026) में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखता है और अपने दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है। ?24,104 करोड़ के बजट के साथ, यह योजना 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 207 जिलों में कार्यान्वित हो रही है और लगभग 48.18 लाख जनजातीय नागरिकों तक पहुँच रही है।

सरकार का एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर संस्थापित किया गया एक परिवर्तनकारी मिशन है। इसका लक्ष्य 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों में बुनियादी सेवाओं की 100 प्रतिशत उपलब्धता और समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यह 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 पहलों के समन्वय के माध्यम से संचालित है।

जनजातीय उत्पादों का जियो–टैगिंग, ट्राइबल बिज़नेस कॉन्क्लेव तथा अन्य पहलें जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के सार्थक कदम हैं। इन प्रयासों से जनजातीय समाज अलग–अलग समूहों से राष्ट्रीय मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सा बन सका है।

शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में प्रयास

जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण की इस नीति–परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, मैंने झारखंड, तेलंगाना और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (श्वरूक्र) के विस्तार पर जोर दिया था, ताकि अधिक से अधिक जनजातीय छात्र इसका लाभ ले सकें।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सरकार ने 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 479 विद्यालय पहले से ही क्रियाशील हैं, और लगभग 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं।

यह भी हर्ष का विषय है कि सरकार ने जनजातीय नेताओं की जीवनियों को अमर बनाने की पहल की है। अब तक 10 राज्यों में 11 अत्याधुनिक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 4 संग्रहालयों का उद्घाटन किया जा चुका है।

मैं उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के साथ उपस्थित था, जब उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क–व–स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, रांची का दौरा किया। ये संग्रहालय डिजिटल और इमर्सिव तकनीक का उपयोग करते हुए इतिहास के पन्नों को जीवंत कथा में बदलते हैं, जो जनजातीय वीरों के बलिदान को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्ष

जनजातीय नेता और उनके आंदोलन हमें निरंतर यह स्मरण कराते हैं कि स्वतंत्रता और गरिमा की लड़ाई, भारत के जनजातीय अंचलों के जंगलों और पहाड़ियों में गहराई से बसी हुई थी। उनका साहस, त्याग और अटूट जज़्बा आज भी सामाजिक न्याय, पर्यावरण संतुलन और मानवाधिकारों के आंदोलनों को प्रेरित करता है।

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने भले ही केवल 25 वर्षों का जीवन जिया, परंतु उन्होंने देशभक्ति की जो ज्वाला प्रज्वलित की है, वह आने वाले 2,500 वर्षों तक भी प्रज्वलित रहेगी। यह कहना उचित होगा कि — मनुष्य आएँगे और चले जाएँगे, पर धरती आबा और अन्य जनजातीय वीरों की विरासत सदैव अमर रहेगी।

जय हिन्द! जय भारत!

भारत के श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में, श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता

लेखक
एस.पी. तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव, ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी)

भारत का कार्य जगत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। देश की श्रमशक्ति को लिखित अनुबंधों, पर्याप्त मजदूरी और व्यापक सामाजिक सुरक्षा द्वारा समर्थित औपचारिक रोजगार में तेजी से जगह मिलनी चाहिए ताकि विकास के लाभ सभी के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण आजीविका में बदल सकें। पुराने विनियामक ढांचों के बने रहने के चलते, आंशिक रूप से, औपचारिकीकरण की गति और उद्यमों की सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण नौकरियां सृजित करने की क्षमता सीमित हो गई है। वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थितियों के संबंध में पारित चार श्रम संहिताएं 2002 में रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता वाली द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा परिकल्पित लंबे समय से लंबित सुधारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस श्रम आयोग का मिशन तत्कालीन मौजूदा श्रम ढांचे को संहिताबद्ध, सरल और संशोधित करना था। ये नई संहिताएं देश के श्रम परिदृश्य को आधुनिक बनाने और संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। सभी राज्यों में इनका एकसमान कार्यान्वयन अब एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है।

ये नई संहिताएं 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाती हैं। इन कानूनों में से कई बीसवीं सदी के मध्य के हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य न केवल कानूनों का विलय करना है, बल्कि श्रमिकों/कर्मचारियों की विभिन्न परिभाषाओं को एक सरल परिभाषा में बदलना भी है। प्रत्येक संहिता श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुदृढ़ करती है और साथ ही नियोक्ताओं के लिए स्पष्टता और पूर्वानुमेयता प्रदान करती है।

उचित मजदूरी और श्रम की गरिमा–वेतन संहिता, 2019 प्रत्येक श्रमिक को श्रम की गरिमा का सम्मान करने वाला वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करके, यह संहिता इस बात की गारंटी देती है कि कोई भी श्रमिक, चाहे वह किसी भी पेशे या स्थान से जुड़ा हो, एक बुनियादी मानक आय से वंचित नहीं रहेगा। उद्योग की अनुसूची को समाप्त करने से सार्वभौमिक वेतन का मार्ग प्रशस्त होता है।

समय पर भुगतान के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। इससे देरी की वह समस्या दूर हुई है, जो पहले परिवारों को कर्ज में धकेल देती थी। अब कर्मचारी अप्रदत्त वेतन या बोनस का दावा आसानी से कर सकते हैं और ऐसे विवादों में सबूत पेश करने का भार नियोक्ता पर होता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है।

साथ ही, यह संहिता उद्यमों के लिए अनुपालनों को सुव्यवस्थित करती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड–कीपिंग, एकल पंजीकरण एवं एकीकृत रिटर्न कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और हेरफेर की आशंकाओं को घटाते हैं।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार–सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 आजाद भारत में कल्याण के सबसे समावेशी विस्तारों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित नौ प्रमुख कानूनों को एकीकृत करके, यह संहिता एक ऐसी एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है जो पारंपरिक और भविष्य के कार्य, दोनों को कवर करती है।

यह पहली बार है जब गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय श्रमशक्ति का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक श्रमिक को ई–श्रम पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जाएगा और एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व सहायता जैसे लाभों का सीधा वितरण संभव हो सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय व राज्य सामाजिक सुरक्षा कोष बनाए जायेंगे कि ऐप–आधारित डिलीवरी पार्टनर या निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूर जैसे श्रमिक भी अब सुरक्षा के दायरे से बाहर न रहें और निधियों का समग्र प्रबंधन संभव हो।

इस संहिता में करियर केन्द्र, डिजिटल एवं भौतिक प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं जो व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श और रोजगार सेवाएं प्रदान करेंगे। यह संस्थागत समर्थन कल्याण को बहु–रोजगार क्षमता से जोड़ेगा, जिससे श्रमिकों को असुरक्षा की स्थिति से निकलकर अवसर की दिशा में बढ़ने में मदद मिल सकेगी।

कार्यस्थल पर सुरक्षा, गरिमा और समानता–व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता), राष्ट्र निर्माण करने वालों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी का एक संदेश है। 卐प्रतिष्ठान卐 की परिभाषा को व्यापक बनाकर, यह संहिता उन लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जो पहले सुरक्षा कानूनों के दायरे में नहीं आते थे।

यह श्रमिकों के निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य करती है और नियोक्ताओं से कर्मचारियों पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखने की अपेक्षा करती है। राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन बदलती औद्योगिक परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा मानकों का विकास सुनिश्चित करता है। ओएसएच संहिता लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करती है। महिला श्रमिकों को सभी प्रतिष्ठानों और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति है, बशर्ते पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। इससे अधिक संख्या में महिलाओं को श्रम बल में शामिल होने व बने रहने का अधिकार मिलता है। प्रवासी श्रमिकों को भी एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली के जरिए मान्यता हासिल होती है। इससे कल्याणकारी योजनाओं और आवागमन संबंधी लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है और बेहतर जीवन एवं आजीविका सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढांचे की निगरानी संभव होती है।

कैंटीन और शौचालय जैसी सुविधाएं अब निचले पायदान तक अनिवार्य हैं और ऐसे प्रावधानों के निर्धारण के क्रम में ठेका श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। ये उपाय न्यूनतम अनुपालन से हटकर श्रमिकों के कल्याण के प्रति वास्तविक चिंता की दिशा में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं।

संवाद और औद्योगिक सद्भाव–

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों में स्पष्टता लाती है और एक एकीकृत ढांचे के साथ तीन पुराने अधिनियमों की जगह लेती है। इसके तहत बीस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिकायत निवारण समितियां स्थापित करना अनिवार्य है ताकि विवादों के हड़ताल या मुकदमेबाजी में बदल जाने से पहले ही उनका शीघ्र समाधान उद्यम स्तर पर सुनिश्चित हो जाए।

ट्रेड यूनियनों को एक समझौतावादी संघ या परिषद की अवधारणा के जरिए मान्यता हासिल होती है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी को बल मिलता है और श्रमिकों को अपने कार्यस्थल को आकार देने में एक प्रभावी भागीदारी हासिल होती है। छंटनी का सामना कर रहे श्रमिक अब 30 दिन का नोटिस और पर्याप्त मुआवजा पाने के हकदार हैं। यह एक मानवीय सुधार है, जो आजीविका की सुरक्षा का सम्मान करता है। छंटनीग्रस्त श्रमिकों के लिए एक पुनः कौशल निधि (रिस्किलिंग फंड) की स्थापना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देती है, जो बदलती अर्थव्यवस्था में सीखने और अनुकूलनशीलता को महत्व देती है। हड़ताल के अधिकार से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बंदी या तालाबंदी की आसान मंजूरी के लिए उद्योगों के लिए श्रमिकों की सीमा को बढ़ाकर 300 तक करने के प्रावधान पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इस संहिता द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त निश्चित अवधि का रोजगार, उद्योग जगत को लचीलापन प्रदान करता है और साथ ही नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में समानता की गारंटी देता है। यह कदम आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों और उसमें काम करने वालों के औचित्य एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

कार्यान्वयन अब क्यों जरूरी– विभिन्न विकासशील देशों से मिले साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि श्रम सुधारों ने आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ते टैरिफ और व्यापार के बदलते पैटर्न से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों की पृष्ठभूमि में, भारत को अपने नए श्रम कानूनों को तत्काल लागू करना जरूरी है। सरल एवं पारदर्शी कानून निवेश को आकर्षित करेंगे, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देंगे और श्रमिकों की गरिमा को बनाए रखेंगे। समय पर अधिसूचना भारत को विकसित देशों का दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

एक ऐसे दौर में जब स्वचालन और डिजिटलीकरण पारंपरिक नौकरियों के खत्म हो जाने का खतरा पैदा कर रहे हैं, ये संहिताएं संतुलित विकास का एक ऐसा ढांचा प्रदान करती हैं जो तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवीय गरिमा को बनाए रखता है। सभी राज्यों में इनके कार्यान्वयन से एक समान मानक बनेंगे, अस्पष्टता कम होगी और नौकरियां आसानी से सुलभ होंगी।

आगे की राह–ये चार संहिताएं एक ऐसे आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की महत्वाकांक्षा की रीढ़ हैं, जो आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। ये संहिताएं निरीक्षकों को सुविधाप्रदाता में बदल देती हैं, पुराने एवं परस्पर विरोधी कानूनों को स्पष्ट व सुसंगत कानूनों से बदल देती हैं और श्रमिकों के कल्याण को आर्थिक नीति के केन्द्र में रखती हैं।

कुछ शर्तों के साथ इन सुधारों की भावना केवल एकीकरण में ही नहीं, बल्कि करुणा में भी निहित है। ये सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि कारखाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, हर कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और संरक्षा मिले। श्रमिकों के लिए, ये सुधार निष्पक्षता और अवसर का वादा करते हैं। इसलिए, इन संहिताओं को शीघ्रता और एकरूपता के साथ लागू करना न केवल प्रशासनिक तात्कालिकता, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का भी विषय है ताकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके जहां विकास सबका साझा हो, काम का सम्मान हो और भारत की प्रगति में योगदान देने वाले हर हाथ की रक्षा हो एवं उनके जीवनयापन में आसानी हो।